www.tamsasanket.com
वर्ष: 06 || अंक 45 || लखनऊ
शुक्रवार
15 मई 2026 || पृष्ठ: 04 || मूल्य: ₹ 2
आज़ादी का अमृत महोत्सव
समूह संपादक- डॉ. ओ.पी. मिश्रा
https://epaper.tamsasanket.com

दैनिक तमसा संकेत

लखनऊ व अम्बेडकर नगर से एक साथ प्रकाशित
डॉ. लोहिया की जन्म भूमि से सर्वप्रथम प्रकाशित समाचार पत्र

मौसम
सूर्योदय: 05:19
सूर्यास्त: 06:47
अधिकतम: 38°00
न्यूनतम: 27°00

पेज 03

विशेष समाचार
पेपर लीक से हर साल छात्रों के... >> पेज 02
ट्रक में घुसी स्कार्पियो, परिवार के... >> पेज 04
तलाक की खबरों के बीच पहली बार...

वकील बनकर कोर्ट में पेश हुईं ममता

चुनावी हिंसा से जुड़े मामले में पैरवी की, बाहर निकलीं तो बुआ चोर-भतीजा चोर के नारे लगे

सुनवाई

तमसा संकेत, एजेंसी

कोलकता। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस चीफ ममता बनर्जी एक बार फिर काला कोट पहनकर कोर्ट में दलीलें देने पहुंचीं। ममता गुरुवार को कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुजॉय पाल और जस्टिस पार्थसारथी सेन के सामने पेश हुईं। मामला हाल के राज्य विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद हुई चुनावी हिंसा से जुड़ी जनहित याचिका का था। सुनवाई के दौरान ममता ने कोर्ट को बताया कि राज्य में हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों के बाद बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। इसमें बुलडोजर एक्शन भी शामिल है। पुलिस FIR दर्ज करने की परमिशन नहीं दे रही है। उन्होंने TMC कार्यकर्ताओं पर हमले, आगजनी और हत्याओं के आरोप लगाते हुए कोर्ट से सुरक्षा और निष्पक्ष जांच की मांग की। इधर, सुनवाई के बाद जब ममता कोर्ट रूम से बाहर निकलीं, तो गलियारों में मौजूद वकीलों की भीड़ ने उन्हें घेर लिया। ये सभी ममता को देखकर बुआ चोर-भतीजे चोर के नारे लगाने लगे।

बनर्जी वकील का गाउन पहनकर हाई कोर्ट पहुंचीं, उनके साथ तृणमूल कांग्रेस की वरिष्ठ नेता चंद्रिमा भट्टाचार्य और कल्याण बनर्जी भी थे। यह मामला तृणमूल कांग्रेस की ओर से वकील शीर्षन्या बंद्योपाध्याय द्वारा दायर एक जनहित याचिका से जुड़ा है, जिसमें 2026 के विधानसभा चुनाव के नतीजों की घोषणा के बाद पार्टी कार्यालयों पर हमलों और उसके कार्यकर्ताओं के खिलाफ हिंसा का आरोप लगाया गया है। याचिकाकर्ता के अनुसार, चुनाव के बाद कई तृणमूल नेताओं और कार्यकर्ताओं को कथित तौर पर अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया, जबकि उनमें से कई पर 'तृणमूल कांग्रेस से उनके जुड़ाव के कारण' हमला किया गया।

कोर्ट रूम में वकीलों के बीच बैठीं ममता बनर्जी, वे अपनी सिग्नेचर सफेद साड़ी पर काला कोट पहने नजर आईं।

वकील की पोशाक में हाई कोर्ट पहुंचीं ममता

ममता बनर्जी गुरुवार को कोलकाता हाई कोर्ट में पूरी वकीली पोशाक में पहुंची थीं। उन्होंने अपनी सफेद–नीली बॉर्डर वाली साड़ी के ऊपर काला कोट और सफेद बैंड पहना हुआ था। वह मुख्य न्यायाधीश सुजय पाल और जस्टिस पार्थ सारथी सेन की खंडपीठ के सामने पेश हुईं। उन्होंने विधानसभा चुनाव के बाद कथित हिंसा से जुड़े जनहित याचिका मामले में अदालत के सामने तस्वीरें और कथित पीड़ितों की सूची भी रखी। सुनवाई के दौरान ममता बनर्जी ने अदालत से 'बंगाल के लोगों की रक्षा करने' की अपील की और आरोप लगाया कि राज्य में हिंसा, लूटपाट और डराने–धमकाने की घटनाओं पर कार्रवाई नहीं हो रही है।

ममता के पास एलएलबी की डिग्री, एडवोकेट से करियर शुरू किया था

- ममता के इलेक्शन एफिडेविट के अनुसार, उन्होंने 1979 में कोलकाता यूनिवर्सिटी से MA करने के बाद, जोगेश चंद्र चौधरी कॉलेज (कोलकाता) में LLB कोर्स में एडमिशन लिया था। 1982 में उनका LLB पूरा हो गया था।
- ममता ने 1980 के दशक में कलकत्ता हाईकोर्ट में एक वकील के रूप में प्रैक्टिस की थी। उनका यह करियर लंबे समय तक नहीं चला, क्योंकि इसी दौरान वे पूरी तरह सक्रिय राजनीति में उतर गईं।
- ममता लंबे समय तक प्रैक्टिस करने वाली वकील नहीं रहीं। वे लॉ ग्रेजुएट हैं और कोर्ट की कार्यप्रणाली और संवैधानिक प्रक्रियाओं की समझ रखती हैं।

टीएमसी का दावा- बंगाल में चुनाव बाद हिंसा की 2000 घटनाएं

पश्चिम बंगाल का 2021 का विधानसभा चुनाव सबसे हिंसक चुनाव था, जिसमें हिंसा की 300 घटनाएं हुईं और 58 लोगों की मौत हुई थी। भाजपा का दावा है कि 2026 चुनाव के बाद उसके 4 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या की गई है। हालांकि TMC के मुताबिक हिंसा की 2,000 से अधिक शिकायतें सामने आई हैं, लेकिन किसी में FIR दर्ज नहीं की गई है। उसके 5 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की भी हत्या की गई है।

“बीसीआई ने कहा है कि सारी जानकारी केवल आधिकारिक रिकॉर्ड के आधार पर दी जाए। इसमें नामांकन रजिस्टर, स्टेट रोल रिकॉर्ड, प्रैक्टिस सर्टिफिकेट, निलंबन या प्रैक्टिस बंद करने से जुड़े दस्तावेज और अन्य फाइल रिकॉर्ड शामिल होंगे।

बीसीआई ने राज्य बार काउंसिल से निम्नलिखित जानकारियां मांगी हैं:-

क्या ममता बनर्जी का नाम पश्चिम बंगाल स्टेट बार काउंसिल में दर्ज है? यदि हां, तो उनका एनरोलमेंट नंबर क्या है?
उनका नामांकन किस तारीख को हुआ था?
क्या उनका नाम अभी भी स्टेट रोल ऑफ एडवोकेट्स में मौजूद है?
मुख्यमंत्री रहते हुए क्या उन्होंने स्वेच्छा से प्रैक्टिस रोकने या निलंबित करने की कोई सूचना दी थी?
यदि ऐसी कोई सूचना दी गई थी, तो उसकी तारीख, आवेदन की प्रति और उससे जुड़े आदेश उपलब्ध कराए जाएं।
क्या बाद में उन्होंने दोबारा प्रैक्टिस शुरू करने के लिए कोई आवेदन दिया था?
यदि दिया था, तो उसकी तारीख क्या थी और क्या उसे स्वीकार किया गया?
क्या उनके नाम पर कोई वैध सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मौजूद है? यदि है, तो उसकी वर्तमान स्थिति क्या है?
क्या मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान या उसके बाद उनकी प्रैक्टिस से जुड़ा कोई अन्य रिकॉर्ड, आदेश या संचार उपलब्ध है?

अखिलेश के भाई प्रतीक को ससुर ने दी मुखाग्नि

सपा प्रमुख ने चिता पर लकड़ी रखी, प्रणाम किया, भतीजी को चॉकलेट खिलाई

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक गुरुवार दोपहर पंचतत्व में विलीन हो गए। लखनऊ में पत्नी अपर्णा के पिता यानी प्रतीक के ससुर अरविंद सिंह बिष्ट ने चिता को मुखाग्नि दी। अखिलेश ने भाई की चिता पर लकड़ी रखी और अंतिम प्रणाम किया। प्रतीक की दोनों बेटियां प्रथमा और पद्मजा भी श्मशान घाट पर मौजूद रहीं। दोनों ने पिता की चिता पर लकड़ी रखी। प्रतीक की छोटी बेटी पद्मजा अपने ताऊ अखिलेश के पास थी। अखिलेश ने उससे बात की और चॉकलेट खिलाई।

>> (शेष पेज 04 पर)

19 राज्य : यूटी में एसआईआर का ऐलान, यहां 37 करोड़ वोटर्स

30 मई से 23 दिसंबर के बीच होगा वेरिफिकेशन, पंजाब

तमसा संकेत, एजेंसी

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने गुरुवार को हरियाणा, झारखंड, उत्तराखंड, दिल्ली समेत 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में स्पेशल इंटेसिव रिवीजन (SIR) की घोषणा की है। यह SIR का तीसरा फेज होगा। पूरी प्रक्रिया 30 मई से 23 दिसंबर तक चलेगी। इस दौरान 36.73 करोड़ वोटरों का वेरिफिकेशन होगा। जिन राज्यों में SIR होगा, उनमें पंजाब, उत्तराखंड और मणिपुर में अगले साल विधानसभा चुनाव हैं। अन्य 13 राज्यों में 2028 और 2029 में चुनाव होंगे। SIR के पहले और दूसरे फेज में 10 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश कवर हो चुके हैं। SIR के बाद बिहार, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी और असम विधानसभा चुनाव में भाजपा जीती है। केरल में कांग्रेस गठबंधन और तमिलनाडु में TVK ने जीत हासिल की है। असम में स्पेशल रिवीजन (SR) हुआ। यहां भी भाजपा सरकार की वापसी हुई। चुनाव आयोग ने बताया कि तीसरे फेज की SIR प्रक्रिया में 3.94 लाख बूथ लेवल अधिकारी (BLO) तैनात होंगे। BLO की मदद के लिए राजनीतिक पार्टियों की तरफ नियुक्त 3.42 लाख बूथ लेवल एजेंट (BLA) भी शामिल रहेंगे। SIR के तीसरे फेज के बाद हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को छोड़कर पूरे देश में SIR प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तीनों बचे हुए राज्यों में खराब मौसम और जनगणना के कारण SIR के शेड्यूल की घोषणा बाद में की जाएगी।

फास्ट न्यूज

राहुल 22 साल में 54 बार विदेश गए : भाजपा

नई दिल्ली। भाजपा ने लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की विदेश यात्राओं पर सवाल उठाया। गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा प्रवक्ता और सांसद संबित पात्रा ने कहा- राहुल गांधी ने पिछले 22 साल में 54 विदेश यात्राएं की हैं। सितंबर 2025 में सीक्रेट यात्राएं भी की हैं। उन्होंने दावा किया कि हर विदेश दौरे में राहुल के साथ 3-4 लोग भी जाते थे।

लाल किला ब्लास्ट मामले में 7500 पेज की चार्जशीट

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली को दहलाने वाले कार बम धमाके मामले में NIA ने 7500 पन्नों की चार्जशीट पेश कर दी है। दिल्ली की पटियाला हाउस स्थित NIA स्पेशल कोर्ट में दाखिल इस चार्जशीट में 10 आरोपियों को नामजद किया गया है। 10 नवंबर, 2025 की शाम लाल किले के पास हुए इस धमाके में 11 लोगों की मौत, जबकि कई घायल हुए थे। NIA की जांच में पता चला है कि सभी आरोपी आतंकी संगठन सार गजवत-उल-हिंद और अल-कायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट (AQIS) से जुड़े थे। गिरफ्तार किए गए 8 आतंकियों में 5 पेशे से डॉक्टर हैं। चार्जशीट में मुख्य आरोपी पुलवामा निवासी डॉ. उमर उन नबी का भी नाम है।

वीडी सतीशन केरलम के सीएम होंगे

तिरुवनंतपुरम। कांग्रेस नेता वी डी सतीशन केरलम के नए सीएम होंगे। कांग्रेस ने राज्य के चुनाव नतीजे घोषित होने के 10 दिन बाद गुरुवार को इसका ऐलान किया। 61 साल के सतीशन पारावूर सीट से विधायक हैं। घोषणा के बाद सतीशन गुरुवार को केरलम के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मिले और सरकार बनाने का दावा पेश किया।

सबरीमला में महिलाओं की एंट्री मामला, एससी का फैसला सुरक्षित

16 दिन सुनवाई चली, कोर्ट ने केंद्र, धार्मिक संगठनों और याचिकाकर्ताओं की दलीलें सुनीं

तमसा संकेत, एजेंसी

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमला मंदिर समेत विभिन्न धार्मिक स्थलों पर महिलाओं की एंट्री और उनकी धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े मामलों की सुनवाई गुरुवार को पूरी कर ली है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता में 9 जजों वाली बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने 16 दिन तक केंद्र, धार्मिक संगठनों और याचिकाकर्ताओं की दलीलें सुनीं। कोर्ट धार्मिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25 और 26 के दायरे, संवैधानिक नैतिकता और धार्मिक प्रथाओं में न्यायिक हस्तक्षेप की सीमा जैसे कई अहम संवैधानिक सवालों पर फैसला देगी। इनमें सबसे अहम मासिक धर्म के उम्र वाली 10 से 50 साल की महिलाओं की सबरीमाला मंदिर में एंट्री का विवाद है। सितंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों वाली बेंच ने महिलाओं के सबरीमला मंदिर में एंट्री पर लगे प्रतिबंध को असंवैधानिक बताते हुए हटा दिया था। बाद में 2019 में इस मुद्दे को बड़ी बेंच को भेजा गया। 16 दिनों की सुनवाई के दौरान 7 संवैधानिक सवालों पर बहस हुई। केंद्र सरकार महिलाओं की एंट्री के विरोध में है। सबरीमाला मामले के साथ मुस्लिम महिलाओं के मस्जिद और दरगाहों में प्रवेश और पारसी महिलाओं के अगियारी में प्रवेश से जुड़े मुद्दे भी बड़ी बेंच को भेजे गए थे। मामले की सुनवाई कर रही 9 जजों की बेंच में CJI जस्टिस बी.वी. नागरत्ना, एम.एम. सुंदरेश, अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, अरविंद कुमार, ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, प्रसन्ना बी. वराले, आर. महादेवन और जॉयमाल्य बागची भी शामिल हैं। केंद्र सरकार ने अदालत में कहा कि सबरीमला मंदिर में मासिक धर्म आयु वर्ग की महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध धार्मिक आस्था और संप्रदायिक स्वायत्तता का विषय है।

>> (शेष पेज 04 पर)

दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्णलता ने शराब नीति केस छोड़ा

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने गुरुवार को शराब नीति घोटाला मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। उन्होंने कहा- ये केस कोई और बेंच सुनेगी। जस्टिस शर्मा ने कहा- कानून के मुताबिक जो जज अवमानना की कार्रवाई शुरू करते हैं वो मुख्य केस नहीं सुन सकते। मैं इस मामले को चीफ जस्टिस के सामने लिस्ट करूंगी ताकि केस की सुनवाई कोई दूसरा जज कर सके। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के अन्य नेताओं के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया है। केजरीवाल के अलावा मनीष सिसोदिया, दुर्गेश पाठक, सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह और विनय मिश्रा शामिल हैं। जस्टिस शर्मा ने कहा कि सोशल मीडिया पर कोर्ट और उनके खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट किए गए। उन्होंने कहा कि केजरीवाल का व्यवहार क्रिमिनल कंटेम्प्ट जैसा है, जिस पर कार्रवाई जरूरी है।

चारधाम यात्रा में 25 दिनों में 40 श्रद्धालुओं की मौत

देहरादून। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार रिकॉर्ड बना रही है। 19 अप्रैल से शुरू हुई यात्रा में 13 मई तक 12 लाख 64 हजार 217 श्रद्धालु चारों धामों के दर्शन कर चुके हैं। लेकिन दूसरी ओर यात्रा के दौरान मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र (SEOC) की 14 मई सुबह 10 बजे जारी रिपोर्ट के अनुसार अब तक चारधाम यात्रा में 40 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा 22 मौतें केदारनाथ धाम में दर्ज की गई हैं। वहीं बद्रीनाथ में 7, यमुनोत्री में 6 और गंगोत्री में 5 श्रद्धालुओं की जान गई है। सरकार लगातार बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं और मेडिकल तैयारियों का दावा कर रही है।

>> (शेष पेज 04 पर)

फैसला : जब सरकार को ही फैसला लेना है, फिर कमेटी में नेता विपक्ष को रखने का दिखावा क्यों

सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सवाल

तमसा संकेत, एजेंसी

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्तों (EC) की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर केंद्र सरकार से सवाल किया। कोर्ट ने कहा- अगर सरकार को ही फैसला करना है तो सिलेक्शन कमेटी में नेता विपक्ष (LoP) को रखकर स्वतंत्रता का दिखावा करने की जरूरत क्या है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने कहा कि CBI डायरेक्टर की सिलेक्शन कमेटी में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) शामिल होते हैं, लेकिन चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाली समिति में कोई स्वतंत्र सदस्य नहीं रखा गया है। कोर्ट 'मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023' को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।

>> (शेष पेज 04 पर)

कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी से पूछा, "अगर प्रधानमंत्री एक नाम चुनते हैं और विपक्ष का नेता दूसरा नाम चुनता है, और दोनों में मतभेद होता है, तो क्या तीसरा सदस्य विपक्ष के नेता के पक्ष में जाएगा?" इस पर अटॉर्नी जनरल ने माना कि शायद ऐसा नहीं होगा। इस पर कोर्ट ने कहा- तो फिर सब कुछ कार्यपालिका ही कंट्रोल कर रही है। ऐसे में विपक्ष के नेता को शामिल ही क्यों करते हैं? वे सिर्फ दिखावटी हो जाते हैं।

6 मई: एससी ने पूछा था- क्या हमारे पास कानून बनवाने का अधिकार

सुप्रीम कोर्ट ने 6 मई को मामले की सुनवाई के दौरान पूछा था कि क्या अदालत संसद को नया कानून बनाने का निर्देश दे सकती है। बेंच ने कहा कि एक याचिका में संसद को कानून बनाने का निर्देश देने की मांग की गई है। लेकिन क्या अदालत ऐसा निर्देश दे सकती है।

12 मई : राहुल बोले- विपक्ष का नेता रबर स्टैंप नहीं

राहुल गांधी ने 12 मई को पीएम आवास पर हुई मीटिंग में नए CBI डायरेक्टर के सेलेक्शन पर अपनी असहमति जताई थी। राहुल ने आरोप लगाया कि चयन के लिए जिन 69 उम्मीदवारों की लिस्ट दी है।

प्रतीक को 13 दिन में 2 बार हार्ट अटैक आया

लखनऊ। अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव को 13 दिन में 2 बार दिल का दौरा (हार्ट अटैक) पड़ा। 30 अप्रैल को लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर प्रतीक फ्लाइट से उतरकर VIP लाउंज की तरफ आ रहे थे। तभी उन्हें सीने में तेज दर्द उठा था। चक्कर आने से चलते-चलते गिर पड़े थे।

सहयोगी उन्हें लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल लेकर गए। डॉक्टरों ने बताया कि प्रतीक को दिल का दौरा पड़ा है। अपर्णा भी हॉस्पिटल पहुंची थीं। उस वक्त प्रतीक की जान 2 वजह से बच गई थी। पहला- दौरा माइनर था। दूसरा- समय रहते वह अस्पताल पहुंच गए थे।

लेकिन, 13 मई को पड़े दिल के दौरे में उनकी जान नहीं बच पाई। सुबह 6.30 बजे जब प्रतीक को सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया था, तब तक उनकी सांसें थम चुकी थीं। इसलिए डॉक्टर बहुत मदद नहीं कर सके। अखिलेश यादव ने प्रतीक को आखिरी बार देखने के बाद भावुक होकर कहा- वो (प्रतीक) अपने स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहता था।

यूपी में 111 मौतों पर रूसी-राष्ट्रपति पुतिन ने शोक जताया

बोले- मेरी गहरी संवेदनाएं, आंधी-बारिश में टिनशेड के साथ 50 फीट उड़ा युवक

आंधी-तूफान

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ/वाराणसी/प्रयागराज/कानपुर। यूपी में आंधी-तूफान और तेज बारिश की वजह से पिछले 24 घंटे में 111 लोगों की मौत हो गई। सबसे ज्यादा 21 मौतें प्रयागराज और 17 मौतें भदोही में हुईं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी इन मौतों पर दुख जताया है। पुतिन ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना शोक संदेश भेजा है। कहा, उत्तर प्रदेश में तूफान के कारण हुई भारी जान-माल की हानि और बड़े पैमाने पर हुई तबाही पर मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। सीएम योगी ने सभी जिलों के प्रभारी मंत्रियों को प्रभावित परिवारों से मुलाकात करने और हालात का जायजा लेने को कहा है। योगी ने कहा, आपदा की इस घड़ी में सरकार पूरी मजबूती के साथ जनता के साथ खड़ी है। राहत के कामों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। बुधवार शाम को गाजियाबाद, वाराणसी, अयोध्या समेत 30 जिलों में तूफान आया।

बरेली में हवा में उड़े युवक का हाथ टूट गया। अस्पताल में इलाज के बाद उसे घर भेज दिया गया।

सम्पादकीय

लोककल्याणकारी दायित्व से पीछे हटती सरकार

एसआईआर के तहत मतदाता सूची से काटे गए लाखों नामों के बाद एक गंभीर आशंका बार-बार उठी कि क्या इन लोगों को नागरिक कहलाने का भी हक नहीं रहेगा। अब बिहार और बंगाल की भाजपा सरकारों ने इन आशंकाओं को सही साबित कर दिया है। बंगाल और बिहार की सरकारों ने कहा है कि जिनके नाम एसआईआर में कट चुके हैं, वे अपने राज्यों में सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे। ज्ञात हो कि पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने सोमवार को अपनी पहली कैबिनेट बैठक की, जिसमें उसने घोषणा की कि राज्य में पिछली सरकारों की सभी सामाजिक योजनाएं जारी रहेंगी, साथ ही टीएमसी के शासन में जिन केंद्रीय कार्यक्रमों को रोका गया था, वे अब उपलब्ध होंगे। हालांकि बैठक में तय हुआ कि न्यायाधिकरणों के समक्ष जिन मतदाताओं के मामले विचाराधीन हैं, उन्हें फैसला होने तक वही सुविधाएं मिलती रहेंगी। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा, 'सरकार के सभी सामाजिक कार्यक्रम, चाहे वे 30 साल पहले शुरू हुए हों या 10 साल पहले, जारी रहेंगे। हालांकि, अब ये सभी योजनाएं पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से संचालित होंगी। किसी भी मृत व्यक्ति, अवैध घुसपैठिए या गैर-भारतीय व्यक्ति को राज्य के नागरिकों के लिए निर्धारित लाभों का लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वहीं बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि 'जिन लोगों के नाम बिहार की मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं, वे राशन और अन्य कल्याणकारी योजनाओं सहित किसी भी सरकारी लाभ के हकदार नहीं होंगे। इसके बाद कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने सोशल मीडिया के जरिए सवाल पूछा है कि एसआईआर के नतीजों के आधार पर बिहार और पश्चिम बंगाल सरकारों के अनुचित निर्णयों के बाद, निम्नलिखित प्रश्न उठता हैः वैसे तो माननीय अदालत से उम्मीद है कि वह श्री चिदंबरम के उठाए सवालों पर तत्काल विचार करे। क्योंकि आजादी के बाद संविधान तैयार करने और वयस्क मताधिकार लागू करने के पीछे मंशा यही थी कि देश के हर नागरिक को उसका हक मिले। सरकार ने व्यवस्था की कि मतदाता सूची तैयार करने के लिए लोगों तक पहुंचा जाए, कोई भी व्यक्ति इस हक से वंचित न रहे। लेकिन एसआईआर के नाम पर बड़े पैमाने पर न केवल लोगों को मताधिकार से वंचित किया गया है, बल्कि अब सरकार की लाभकारी योजनाओं का हक भी उनसे छीना जा रहा है। जिस तरह के दस्तावेज मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए मांगे गए हैं, उन पर पहले ही सवाल उठ रहे थे कि गरीब लोग इन्हें कैसे जुटा पाएंगे, उनके पास ले देकर आधार या राशन कार्ड ही मिलता है। अब जो कुछ आम नागरिकों के पास था, वो भी उनसे छीना जा रहा है। इस तरह तो लोककल्याणकारी सरकार की अवधारणा ही बदल जाएगी। मध्यमवर्ग या उच्च तबके की बेशक अपनी परेशानियां हैं, लेकिन कम से कम दो वक्त की रोटी, कुछ दिनों का रोजगार, सरकारी अस्पतालों में सस्ता इलाज, मुफ्त शिक्षा जैसी मदद की जरूरत उन्हें नहीं है। मगर पिछले छह सालों से जिन लोगों का गुजारा सरकार के दिए पांच किलो राशन से हो रहा हो या मनरेगा के तहत जिन्हें कुछ सौ रूपयों की कमाई होती है वे लोग अब कहां जाएंगे। चुनावों में महिलाओं, बेरोजगारों, किसानों, मजदूरों के लिए जिन योजनाओं का वादा किया जाता है, उनसे भी अब ऐसे लोगों को वंचित रखा जाएगा जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं है। जैसे बिहार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अशोक चौधरी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि 'राज्य में एसआईआर लागू होने के बाद राशन कार्ड धारकों की सूची से लगभग पांच लाख लोगों के नाम हटा दिए गए हैं। वहीं बंगाल के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री अशोक कीर्तनिया ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत नागरिकता के लिए आवेदन करने वाले भी सभी सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन जिनके नाम एसआईआर के माध्यम से हटा दिए गए हैं, वे सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा सकते। इसी तरह बंगाल की शहरी विकास और नगर पालिका मामलों की मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहाः 'हम विश्लेषण करेंगे, जिनके नाम सूची से हटा दिए गए हैं, वे या तो देश के नागरिक नहीं हैं या मर चुके हैं, उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल सकता। गौरतलब है कि नागरिकता से संबंधित मामले, जिनमें नागरिकता छीनना भी शामिल है, नागरिकता अधिनियम, 1955 द्वारा शासित होते हैं, और किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने या नागरिकता रद्द करने का अधिकार केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास है। एसआईआर पर सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाई के दौरान, यह प्रश्न उठाया गया था कि क्या यह नागरिकता की कसौटी है। तब निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया था कि यद्यपि उसके पास नागरिकता निर्धारित करने का अधिकार नहीं है, फिर भी संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत नागरिकता की स्थिति को 'सत्यापित करने का उसका अधिकार निहित है, जिसमें कहा गया है कि 18 वर्ष से अधिक आयु के भारतीय नागरिक मतदाता के रूप में पंजीकृत हो सकते हैं। पिछले साल जुलाई में अदालत में दायर अपने जवाबी हलफनामे में, चुनाव आयोग ने इस बात पर जोर देते हुए कहा थाः 'एसआईआर प्रक्रिया के तहत, किसी व्यक्ति की नागरिकता इस आधार पर समाप्त नहीं होगी कि उसे मतदाता सूची में पंजीकरण के लिए अयोग्य माना जाता है।

पेपर लीक से हर साल छात्रों के साथ देश को हो रहा नुकसान

> गेस पेपर से परीक्षा में कुछ सवाल हूबहू आने की संभावना रहती है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में प्रश्न आने की संभावना बिल्कुल नहीं रहती। इसीलिए जब जांच पड़ताल हुई तो एक-एक कर इसके खुलासे होने लगे। पता चला कि सबसे पहले महाराष्ट्र में पेपर लीक हुआ था।

पेपर लीक के कारण मेडिकल डिग्री प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) परीक्षा रद्द होने के बाद ईमानदार छात्रों के मन में निराशा, गुस्सा, हताशा, हताशा, हताशा और हताशा महसूस की गई। माता-पिता ने इस अवसर पर निजी ट्यूशन कक्षाओं के लिए फीस का भुगतान किया। 3 मई को, NEET देने के बाद, छात्रों ने एक गहरी सांस ली और भविष्य के बारे में सपने देखने लगे, यात्राओं की योजना बनाने लगे। 10 दिन से भी कम समय के बाद, परीक्षा आयोजित करने वाली नेशनल टेस्टिंग कंडक्टिंग एजेंसी (NTA) का कहना है कि परीक्षा रद्द कर दी गई क्योंकि परीक्षा से पहले अधिकांश प्रश्न टूट गए थे। परीक्षा में शामिल होने वाले सभी लोगों की अब फिर से जांच की जाएगी। डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा NEET भी 'लीकतंत्र' का शिकार हो गई। 22 लाख 79 हजार छात्रों ने दिन-रात मेहनत करके परीक्षा दी। परीक्षा खत्म होने के बाद जो मानसिक दबाव कम हुआ था, वो फिर से बढ़ गया है। लीकतंत्र ने उनकी मेहनत, उनका समय और उनके सपनों पर चोट पहुंचाई है। ये पहली बार नहीं है, जब किसी बड़ी परीक्षा को लीकतंत्र ने अपना शिकार बनाया हो। पिछले 11 सालों में 100 से अधिक बार केंद्रीय और भर्ती परीक्षाएं पेपर लीक और अनियमितताओं की भेंट चढ़ चुकी हैं। इस बार जिस NEET परीक्षा का पेपर लीक हुआ है, उसकी जांच केंद्र सरकार ने CBI को सौंप दी है। CBI की जांच में आने वाले दिनों में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं और यह भी साफ होगा कि इस पूरे खेल में कौन-कौन शामिल था। लेकिन उससे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर यह 'लीकतंत्र' काम कैसे करता है। कैसे लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा प्रश्नपत्र परीक्षा से पहले ही बाजार में पहुंच जाता है? कैसे एक संगठित नेटवर्क मेहनत पर पैसे को भारी बना देता है? जैसा कि हमने आपको बताया, लोकतंत्र की तरह 'लीकतंत्र' भी चार अलग-अलग स्तंभों पर खड़ा दिखाई

देता है। पहला स्तंभ वह एजेंसी है, जो NEET जैसी परीक्षाएं आयोजित करवाती है। दूसरा स्तंभ खुफिया तंत्र है, जिसकी जिम्मेदारी संभावित लीक या संदिग्ध गतिविधि का समय रहते पता लगाना होती है।लीकतंत्र का तीसरा स्तंभ पेपर माफिया हैं, जो किसी भी तरह परीक्षा से पहले प्रश्नपत्र हासिल करने की कोशिश करते हैं। लीकतंत्र का चौथा स्तंभ वे खरीदार हैं, जो लाखों रुपये में पेपर खरीदकर ईमानदार छात्रों के हक पर डाका डाल देते हैं। हम आपको लीकतंत्र के इन चारों स्तम्भों के बारे में एक-एक कर विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं कि इस बार लीकतंत्र ने किस तरह सिस्टम को हैक करके ईमानदार बच्चों के सपनों में सेंधमारी कर दी। परीक्षा से करीब 42 घंटे पहले ही क्वेश्चन पेपर के कुछ सवाल 'लीकतंत्र' के हाथ लग चुके थे।लीकतंत्र ने लीक हुए सवालों में कुछ अन्य प्रश्न जोड़कर एक पूरा क्वेश्चन बैंक तैयार किया।छात्रों तक जो क्वेश्चन बैंक पहुंचाया गया, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 300 से ज्यादा सवाल शामिल थे।इनमें से करीब 150 सवाल हूबहू NEET UG 2026 के प्रश्नपत्र में पूछे गए।यानि 720 अंकों की परीक्षा में लगभग 600 नंबर के सवाल पहले से ही लीकतंत्र के बनाए क्वेश्चन बैंक में मौजूद थे। व्हाट्सऐप पर 'प्राइवेट माफिया' नाम से एक ग्रुप भी बनाया गया था। इस ग्रुप में करीब 400 सदस्य जुड़े हुए थे। आरोप है कि इस ग्रुप का इस्तेमाल विशेष रूप से लीक किए गए 'गेस पेपर' और सवालों को सर्कुलेट करने के लिए किया गया। टेलीग्राम पर भी एक चैनल बनाया गया था, जिसमें NEET का असली पेपर होने का दावा किया जा रहा था। 1 मई से ही व्हाट्सऐप और टेलीग्राम पर प्रश्नपत्र की PDF फाइलें तेजी से शेयर की जा रही थीं। जांच एजेंसियों ने व्हाट्सऐप चैट और टेलीग्राम रिकॉर्ड्स को अहम सबूत के तौर पर जुटाया है। इन डिजिटल रिकॉर्ड्स से यह पता चला है कि पेपर लीक का नेटवर्क सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए कितनी तेजी से फैलाया गया। एक तरफ जांच एजेंसियां सबूत इकट्ठा कर रही हैं, तो दूसरी तरफ इस पूरे नेटवर्क से जुड़े लोगों पर शिकंजा भी कसना शुरू हो गया है। राजस्थान के अलग-अलग शहरों से कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। जयपुर में मनीष नाम के शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिस पर पेपर लीक नेटवर्क से जुड़े होने का शक है। डॉक्टर भीमराव आंबेडकर ने कहा था कि 'मेहनत करने वाले विद्यार्थियों के साथ अन्याय, देश के भविष्य के साथ अन्याय होता है'। और ये अन्याय देश के करीब 23 लाख छात्रों के साथ हुआ है। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। 2024 में भी NEET परीक्षा पेपर लीक और अनियमितताओं के आरोपों से घिर गई थी। बिहार और झारखंड में मामले की जांच हुई, जिसमें पेपर लीक के सबूत मिले थे और कई गिरफ्तारियां भी हुई थीं। हालांकि उस समय तो सुप्रीम कोर्ट ने पूरी परीक्षा रद्द करने से इनकार कर दिया था। लेकिन कुछ परीक्षा केंद्रों पर 1539 कैंडिडेट्स की दोबारा परीक्षा कराई गई थी। इसके अलावा 2018, 2021 और 2022 में भी NEET परीक्षा में अनियमितताओं और गड़बड़ियों के आरोप लगे थे। इन मामलों की जांच अब तक CBI कर रही है। और यह समस्या सिर्फ NEET तक सीमित नहीं रही। जब मेडिकल कॉलेजों में दाखिला NEET के जरिए नहीं होता था, तब भी पेपर लीक का खेल जारी था। 2011 में देश के सबसे प्रतिष्ठित अस्पताल एम्स की एंट्रेंस परीक्षा में पेपर लीक हुआ था। जांच हुई लेकिन कार्रवाई के नाम पर रस्म अदायगी हुई थी। एक बार फिर वही हुआ है। प्रश्नपत्र फिर लीक हुआ है। लेकिन इस बार मामला पहले से कहीं ज्यादा बड़ा है, क्योंकि पहली बार पूरी NEET परीक्षा ही रद्द कर दी गई है। देशभर में छात्र सड़कों पर उतर आए हैं। कहीं विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, तो कहीं छात्र और अभिभावक अपनी मेहनत बर्बाद होने पर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं।

■ अशोक भाटिया

होर्मुज की तपिश में सरकार की छाँव

- ऑफ होर्मुज बंद होने से देश की सरकार को हो रहा प्रतिदिन 1000 करोड़ का नुकसान।
- मोदी सरकार की दूरदर्शिता से सभी घरों में जलते रहे चूल्हे, चलते रहे वाहन।
- म्हालात बताते हैं कि बढ़ सकता है ऊर्जा संकट।
- म्जनता की समझदारी व सहयोग ही देगा सरकार को इस मुसीबत से लड़ने की ताकत।

घर-परिवार हो या कोई देश आकस्मिक आपदा किसी पर भी कभी भी आ सकती है। विगत दिनों में ईरान और अमेरिका के युद्ध के चलते होर्मुज बंद हो गया, जिसके कारण जहाजों की आवाजाही बंद हो गई। युद्ध के शुरूआती दौर में तो यह लगा था कि तेल और गैस की किल्लत से सभी जगह त्राहि-त्राहि मच जायेगी लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ। सभी घरों में चूल्हे जलते रहे, वाहन चलते रहे, बच्चों की पढाई सुव्यवस्था के साथ चलती रही। यह सब कुछ तभी संभव हो सका क्योंकि हमारा मुखिया, हमारा संरक्षक जिम्मेदार और दूरदर्शी है। हमारी सरकार ने कुशल नेतृत्व के साथ इस मुसीबत की घड़ी में अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए बढ़ती कीमतों के बोझ को अपने तक ही सीमित रखा, जनता को उस तकलीफ से रूबरू ही नहीं होने दिया। जबकि वास्तविकता तो यह है कि हमारी तेल कंपनियों को प्रतिदिन रू. 1000 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ रहा है, अर्थात थोड़े में कहें तो हमारी सरकार को इस युद्ध के कारण रू. 68,000 करोड़ का भारी नुकसान हुआ है। इसके अलावा इस युद्ध का बोझ हमारे तेल भंडारों पर भी पड़ रहा है, उनका स्तर निरंतर नीचे गिर रहा है और जिसको बनाये रखने में निवेश की आवश्यकता पड़ रही है। इस सब का असर सरकार के सेंट्रल एक्साइज पर भी पड़ रहा है। यानी तीन अलग-अलग दिशाओं में भारत को नुकसान उठाना पड़ रहा है। भारी नुकसान के चलते निरंतर गिरती अर्थव्यवस्था को समय रहते सुधारना ही होगा और इसके लिए सरकार के साथ प्रत्येक नागरिक का भी दायित्व है कि वो अपनी भागीदारी समझे। ऐसे कठिन समय में जब आर्थिक मार हर घर, हर व्यक्ति तक पहुँच गई हो, गाड़ियां खड़े होने के कगार पर हों, किसी भी सरकार के लिए बहुत आसान रास्ता था इस आर्थिक बोझ को जनता के ऊपर डालकर अलग हो जाना। लेकिन हमारी संवेदनशील सरकार ने अपनी सूझ बूझ से न केवल जनता को राहत दी बल्कि अपनी नीतिगत कुशलता से जनता को ऐसा छत्र दिया जिससे जनता का सामान्य जीवन अस्त व्यस्त होने से बच गया। युद्ध न रुकने से जहाँ वैश्विक ऊर्जा संकट निरंतर बढ़ता ही जा रहा है वहीं होर्मुज का रास्ता साफ होने के भी कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि भविष्य में युद्ध विराम हो भी गया तो स्थिति को संभलने में कम से कम चार महीने लग जाएंगे, जिसके चलते अधिक समय तक तेल और गैस के दाम उच्च स्तर पर बने रह सकते हैं। परन्तु युद्ध के इस ग्यारहवें सप्ताह में सरकार द्वारा अपनाएं वर्तमान मॉडल को यदि और आगे खींचा गया तो इसके प्रतिकूल प्रभाव हमारी अर्थयवस्था पर पडने लगेंगे। इन परिस्थितियों में हमारे सामने तीन चुनौतियां हैं- पहली चुनौती तेल भंडार से जुड़ी है। भारत का तेल भंडार आज 5.33 मिलियन टन पर है, जो लगभग दो सप्ताह की आवश्यकता पूरी कर सकता है। आईईए मानक नब्बे दिनों का है। चंडीखोल, पादुर और बीकानेर में 6.5 मिलियन टन का दूसरा चरण निर्माणाधीन है, और इसे त्वरित समय-सीमा पर पूरा करना होगा। साथ ही, जापान और दक्षिण कोरिया के बाद भारत ही ऐसा देश है जो 30-दिवसीय एलपीजी भंडार की योजना बना रहा है। इस युद्ध से उत्पन्न संकट से पता चलता है ये हमारी आज की आवश्यकता है। दूसरी चुनौती रिफाइनिंग और घरेलू उत्पादन की है। हमें अपनी रिफाइनिंग क्षमता को बढ़ाना होगा। इसके लिए पहले ही कदम उठाये जा चुके हैं। नुमालीगढ़, जहाँ रु. 34,000 करोड़ की लागत से 3 से 9 एमएमटीपीए तक का विस्तार हो रहा है, उसे समय से पहले परिचालन में लाना होगा। बाड़मेर का संयंत्र अब परिचालन में है। पश्चिमी तट के एकीकृत संयंत्र विभिन्न चरणों में हैं। साथ ही घरेलू कच्चे तेल का उत्पादन, जो आज मांग का मात्र 12 प्रतिशत पूरा करता है, उसको बढ़ाना होगा। तीसरी चुनौती इथनॉल ब्लेंडिंग की है, आज बीस प्रतिशत ब्लेंडिंग करके देश 1.5 लाख करोड़ से अधिक की विदेशी मुद्रा बना पा रहा है। इस कठिन समय में वैकल्पिक ईंधन के माध्यम से एल पीजी की मांग को 70 से 75 हजार टन प्रतिदिन कम किया जा रहा है। आर्थिक नीतियों के जानकारों का कहना है कि यह केवल इसलिए संभव हुआ क्योंकि पीएनजी, मिट्टी का तेल, ईंधन तेल और बायो गैस की वैकल्पिक संरचना संकट आने से पहले ही तैयार कर ली गई थी। जो विशेषज्ञ इस दिशा में लगातार शोध कार्य कर रहे हैं उनका मानना है कि आज की तुलना में आने वाला समय और भी कठिन होगा, तब हमें इस संकट के समय जो हमने व्यय किया उससे उबरना भी होगा और ऐसी योजनाएं जो भविष्य में हमें मजबूती दे सकें उन योजनाओं में निवेश भी करना होगा। विश्व के इस संकट के समय में जब लगभग सभी देशों में पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी गयीं, श्रीलंका, पाकिस्तान में चार दिवसीय कार्य सप्ताह कर दिया गया, फिलीपींस मंे राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल लगा दिया गया, भारत मंे जनजीवन सामान्य बना रहा। न तो भारत में कोई ईंधन राशनिंग हुई न वर्क फ्राम होम हुआ, न ही स्कूल बंद हुए, न ईंधन संकट हुआ और सबसे महत्वपूर्ण बात पेट्रोल के दाम भी नहीं बढ़े। इसे कर दिखाना इतना आसान तो नहीं था पर हमारे प्रधान मंत्री के कुशल नेतृत्व में वर्तमान सरकार ने शिव की भाँति युद्ध से उपजे समस्त गरल को स्वयं ही पी लिया।

भारत अपने कुल... पंकज जायसवाल

संयम और स्वदेशी ही है भारत का सनातन आर्थिक मंत्र और यंत्र

ईरान अमेरिका इजराइल द्वारा शुरू किये गए युद्ध, होर्मुज स्ट्रेट में डबल नाकाबंदी और उससे उपजे वैश्विक मंदी और इकोनॉमिक्स के मेटा इफ़ेक्ट के कारण दुनिया के हालात संकट में हैं. इन संकटों के बीच भारत आज एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहाँ प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शूरू किये गए आर्थिक राष्ट्रवाद, आत्मनिर्भरता और जिम्मेदार उपभोग केवल नारे नहीं बल्कि राष्ट्रीय आवश्यकता बन चुके हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों से सोना खरीदने में संयम बरतने, पेट्रोलियम उत्पादों के उपयोग को कम करने, स्वदेशी को बढ़ावा देने और अनावश्यक आयात पर निर्भरता घटाने की जो अपील की गई, वह केवल एक सामान्य आर्थिक सलाह नहीं है बल्कि एक कुटुंब प्रबोधन की तरह भारत की दीर्घकालिक आर्थिक सुरक्षा, विदेशी मुद्रा संतुलन और आत्मनिर्भर विकास मॉडल का महत्वपूर्ण संकेत आवाहन था। हालांकि जनमानस में यह प्रश्न दौड़ रहा है कि होर्मुज की नाकाबंदी अगर मार्च में ही शूरू हुई थी तो इसका आवाहन इतना देर से क्यों और बीते २ माह में सरकार ने इससे लड़ने के लिए कौन सी नीतियां बनाई क्या तैयारियां कीं ? बंगाल और आसाम चुनाव की शोर में कहीं इस संकट की आहट सुनने में विलम्ब तो नहीं हुआ? फिर भी देर आये दुरुस्त आये की तर्ज पर हमें इस आवाहन को गंभीरता से लेना चाहिए। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, लेकिन इसके बावजूद हमारी कई बुनियादी जरूरतें अभी भी आयात पर आधारित हैं। विशेष रूप से कच्चा तेल, खाद्य तेल और सोना ये तीन ऐसे क्षेत्र हैं जो भारत के आयात बिल पर भारी दबाव डालते हैं। ऊर्जा के मामले में तो हम लगभग ८५ फीसदी दूसरों पर निर्भर है और इस समय ऊर्जा का ही सप्लाई चेन संकट में आ गया है. यदि देश को वास्तव में विकसित राष्ट्र बनना है तो केवल उत्पादन बढ़ाना पर्याप्त नहीं होगा; उपभोग की संस्कृति और आर्थिक व्यवहार में भी परिवर्तन लाना पड़ेगा। जैसे भारत में सोना केवल धातु नहीं बल्कि परंपरा, सामाजिक प्रतिष्ठा और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। विवाह, त्योहार और पारिवारिक निवेश का बड़ा हिस्सा सोने में जाता है लेकिन आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है क्या अत्यधिक सोना खरीदना राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के लिए लाभकारी है? मेरे विचार से यदि सोना अर्थव्यवस्था में सक्रिय रूप से उपयोग नहीं हो रहा, उत्पादन या व्यापार में नहीं लग रहा, बैंकिंग प्रणाली में नहीं आ रहा और केवल लॉकरों में बंद पड़ा है तो वह एक प्रकार का "मृत निवेश" बन जाता है क्योंकि वह पूंजी अर्थव्यवस्था में गति नहीं पैदा करती। जब कोई व्यक्ति सोना खरीदता है, तो उसका बड़ा हिस्सा आयात के माध्यम से विदेशों से आता है। इसका अर्थ है कि देश की विदेशी मुद्रा बाहर जाती है। दूसरी ओर यदि वही पैसा उद्योग, स्टार्टअप, शेयर बाजार, कृषि प्रसंस्करण, विनिर्माण या इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश हो, तो वह रोजगार पैदा करता है, उत्पादन बढ़ाता है और कर राजस्व भी उत्पन्न करता है।

जरा हटके

सुप्रीम कोर्ट ने... डा0 मनोज चन्द्रा

कृषि उद्यमिता और आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था का नया अध्याय है एग्रीजंक्शन योजना

उत्तर प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा देने और ग्रामीण अंचल के शिक्षित युवाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलंबन योजना (एग्रीजंक्शन) एक युगांतरकारी पहल सिद्ध हो रही है। यह योजना केवल सरकारी अनुदान का माध्यम नहीं है, बल्कि ग्रामीण विकास और आधुनिक मेधा को जोड़ने वाला एक जीवंत सेतु है। वर्तमान परिदृश्य में, जहाँ पारंपरिक खेती कई चुनौतियों से जूझ रही है, वहीं एग्रीजंक्शन जैसी पहल एक नई रोशनी बनकर उभरी है, जो कृषि को लाभप्रद व्यवसाय में बदलने का सामर्थ्य रखती है। एग्रीजंक्शन योजना का मुख्य दर्शन ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उत्पादकता को आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के माध्यम से बढ़ाना है। यह योजना कृषि स्नातकों को केवल डिग्री धारक से बदलकर एक सफल उद्यमी के रूप में स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त करती है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह किसानों के लिए एक वन-स्टॉप शॉप के रूप में कार्य करती है। यहाँ मिट्टी की सेहत की जांच से लेकर तकनीकी परामर्श और उच्च गुणवत्ता वाले खाद-बीज एक ही छत के नीचे उपलब्ध हो जाते हैं। भविष्य की दृष्टि से देखें तो यह मॉडल खेती के पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को डिजिटल और आधुनिक बनाने में मील का पत्थर साबित हो रहा है। इससे न केवल खेती की लागत में कमी आ रही है, बल्कि मा0 प्रधानमंत्री जी के किसानों की आय दोगुनी करने के संकल्प को भी प्रबल गति मिल रही है। यह योजना गाँवों से शहरों की ओर होने वाले पलायन को रोकने और युवाओं को अपनी माटी में ही सम्मानजनक आजीविका प्रदान करने का एक सशक्त माध्यम बन चुकी है। प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलंबन योजना उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग की एक अत्यंत महत्वाकांक्षी पहल है। इस योजना के अंतर्गत कृषि, उद्यान या अन्य संबद्ध विषयों में स्नातक कर चुके युवाओं को स्वयं का कृषि सेवा केंद्र खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सरकार इन केंद्रों की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता के साथ-साथ ऋण पर ब्याज की सब्सिडी और शुरुआती वर्षों में

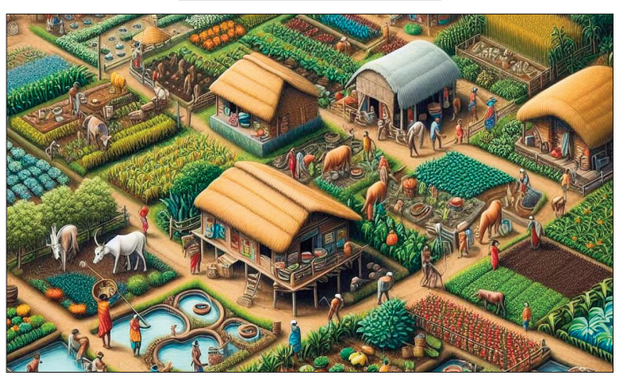

दुकान के किराए में छूट जैसे विशेष प्रोत्साहन प्रदान करती है। एक एग्रीजंक्शन केंद्र पर पहुँचकर किसान न केवल अपनी फसल के लिए आवश्यक संसाधन जुटा सकता है, बल्कि वह सरकारी योजनाओं की सटीक जानकारी और विशेषज्ञों से सीधा संवाद भी कर सकता है। योजना की सफलता इसकी पारदर्शी चयन और प्रशिक्षण प्रक्रिया में निहित है। जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति पूर्ण निष्पक्षता के साथ योग्य अभ्यर्थियों का चयन करती है। इसके पश्चात, चयनित युवाओं को व्यवसाय प्रबंधन, इन्वेंट्री कंट्रोल और आधुनिक कृषि तकनीक की बारीकियों का सघन प्रशिक्षण दिया जाता है। यह प्रशिक्षण उन्हें एक पेशेवर व्यवसायी के रूप में तैयार करता है ताकि वे अपने केंद्र को एक लाभप्रद संस्थान की तरह संचालित कर सकें। इसमें उन युवाओं को विशेष प्राथमिकता दी जाती है जो स्वयं कृषि पृष्ठभूमि से आते हैं। साथ ही, बैंकों के साथ समन्वय स्थापित कर ऋण प्रक्रिया को इतना सुगम बनाया गया है कि पूंजी का अभाव किसी भी मेधावी युवा के उद्यमिता के सपने में बाधक न बन सके। एग्रीजंक्शन योजना भारतीय कृषि की उस पारंपरिक छवि को तोड़ रही है जहाँ खेती को केवल श्रम का कार्य माना जाता था। अब तकनीक और डेटा आधारित खेती का युग है। जब किसानों को इन केंद्रों के माध्यम से मिट्टी परीक्षण की रिपोर्ट और उसके आधार पर उर्वरकों के संतुलित प्रयोग की सलाह मिलती है, तो वे रसायनों के अनावश्यक व्यय से बचते हैं। तकनीक और युवा मेधा का यह संगम भारत में प्रिसीजन फार्मिंग यानी सटीक खेती की बुनियाद रख रहा है। उत्तर प्रदेश के गाँवों में तैयार हो रहा यह नेटवर्क भविष्य की आधुनिक खेती की मजबूत रीढ़ बनेगा। विशेष रूप से कृषि स्नातकों के लिए यह योजना किसी वरदान से कम नहीं है। अब युवा नौकरी की तलाश करने वाले जॉब सीकर के बजाय जॉब क्रिएटर की भूमिका में आ गए हैं। यह योजना उन्हें समाज में एक विशिष्ट पहचान और स्वाभिमान के साथ व्यवसाय करने का अवसर प्रदान करती है। एक कृषि स्नातक जब अपना केंद्र संचालित करता है, तो वह केवल एक विक्रेता नहीं, बल्कि ग्रामीण परिवेश में एक कृषि डॉक्टर के रूप में प्रतिष्ठित होता है। सरकार की वित्तीय सहायता और बैंक ऋण का सुरक्षा कवच उन्हें एक स्थिर स्टार्ट-अप वातावरण देता है, जिससे उनके शैक्षिक ज्ञान का व्यावहारिक उपयोग सुनिश्चित होता है। देश के मा0 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत और ''वोकल फॉर लोकल'' के विजन को एग्रीजंक्शन योजना धरातल पर चरितार्थ कर रही है। यह स्वरोजगार का एक ऐसा तार्किक और तथ्यपूर्ण मॉडल है जो सीधे तौर पर देश की सबसे बड़ी श्रमशक्ति, यानी किसानों से जुड़ा है। जब एक ग्रामीण युवा आत्मनिर्भर बनता है, तो वह अपने केंद्र के माध्यम से कई अन्य लोगों को भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करता है। यह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था में धन के चक्रीय प्रवाह को बढ़ाती है और स्थानीय स्तर पर आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करती है। तथ्यों के धरातल पर देखें तो एग्रीजंक्शन केंद्रों की निरंतर बढ़ती लोकप्रियता इस बात का प्रमाण है कि युवा अब कृषि को एक उच्च स्तरीय व्यावसायिक उपक्रम मान रहे हैं। यह योजना सीधे तौर पर ग्रामीण विकास, बेरोजगारी उन्मूलन और भारत के स्वर्णिम भविष्य के सपने को साकार करने में सहायक सिद्ध हो रही है। उत्तर प्रदेश में केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार की डबल इंजन कार्यप्रणाली ने इस योजना को अभूतपूर्व विस्तार प्रदान किया है। सरकार ने न केवल इसके बजट में भारी वृद्धि की है, बल्कि लाइसेंसिंग की जटिल प्रक्रियाओं और ऋण आवंटन में आने वाली व्यावहारिक बाधाओं को भी सख्ती से दूर किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के विजन के अनुरूप प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर एग्रीजंक्शन केंद्रों की स्थापना का लक्ष्य तीव्र गति से पूरा किया जा रहा है। सरकार इन केंद्रों को खाद, बीज और कीटनाशक वितरण के लाइसेंस प्रदान करने में प्राथमिकता दे रही है। इसके अतिरिक्त, डिजिटल इंडिया अभियान के साथ इन केंद्रों को पोर्टल के माध्यम से जोड़कर व्यवस्था में पूरी पारदर्शिता लाई गई है। प्रदेश सरकार की यह सक्रियता उत्तर प्रदेश के एक ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के लक्ष्य को प्राप्त करने में निर्णायक भूमिका निभाएगी।

चेन्नई के जैमी ओवर्टन चोट के कारण इंग्लैंड लौटे

चोट के कारण आईपीएल के बाकी मैच खेलना मुश्किल, घोष की जगह नोरोन्हा को मौका

चेन्नई, एजेंसी

चेन्नई सुपर किंग्स के तेज गेंदबाज जैमी ओवर्टन दाहिनी जांघ की चोट के कारण इंग्लैंड लौट गए हैं। फ्रेंचाइजी ने बुधवार रात सोशल प्लेटफार्म X पर यह जानकारी दी। हालांकि, टीम ने यह साफ नहीं किया कि वे कितने समय तक बाहर रहेंगे, लेकिन IPL सीजन में बाकी के लीग मैच में उनका खेलना मुश्किल लग रहा है।

वे इस सीजन में चेन्नई के टॉप विकेट टेकर्स की लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं। टीम की सबसे बड़ी चिंता पूर्व कप्तान एमएस धोनी को लेकर बनी हुई है। धोनी पिंडली में खिंचाव के कारण इस सीजन अब तक एक भी मैच नहीं खेल पाए हैं। उनके अलावा ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज स्पेंसर जॉनसन भी अनफिट होने के कारण बेंच पर हैं। मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस भी शुरुआत के तीन मैच नहीं खेल सके थे, जिससे टीम को शुरुआती हार झेलनी पड़ी थी। इतनी चोटों और समस्याओं के बावजूद चेन्नई सुपर किंग्स प्ले-ऑफ की रेस में बनी हुई है। टीम 11 मैचों में 12 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में 5वें स्थान पर है। प्ले-ऑफ में जगह पक्की करने के लिए चेन्नई को अपने बाकी तीनों मैच जीतने होंगे।

टीम का अगला मुकाबला शुक्रवार को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में होगा। उन्होंने महाराजा ट्रॉफी 2025 में मंगलुरु ड्रैगन्स के लिए खेलते हुए उन्होंने 10 पारियों में 253 रन बनाए और ऑफ-स्पिन से 10 विकेट भी लिए थे। चेन्नई ने एलिस को 2024 के मेगा ऑक्शन में 2 करोड़ में खरीदा था।

डेब्यू मैच में घोष का पैर फ्रैक्चर हुआ

CSK ने यह भी बताया कि उसने चोटिल ऑलराउंडर रामकृष्ण घोष की जगह कर्नाटक के ऑलराउंडर मैकनील नोरोन्हा को टीम में शामिल किया है। घोष 3 मई को मुंबई इंडियंस के खिलाफ अपने डेब्यू मैच में चोट लग गई थी। पैर में फ्रैक्चर के चलते उन्हें पूरे सीजन से बाहर होना पड़ा। घोष ने अपने इकलौते मैच में 24 रन देकर 1 विकेट लिया था।

सीएसके के 3 अन्य खिलाड़ी भी चोट से बाहर

ओवर्टन और घोष के अलावा, चेन्नई के 3 अन्य खिलाड़ी भी चोट के कारण बाहर हुए हैं, इनमें खलील अहमद, आयुष म्हात्रे और नाथन एलिस जैसे नाम शामिल हैं।

- **खलील अहमद:** जांघ की मांसपेशियों में खिंचाव के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गए। उन्होंने 5 मैचों में टीम के लिए 2 विकेट लिए थे।
- **आयुष म्हात्रे:** नंबर-3 के बल्लेबाज आयुष भी हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार हुए। उन्होंने इस सीजन 6 मैचों में 177.88 की स्ट्राइक रेट से 201 रन बनाए।
- **नाथन एलिस:** सीजन शुरू होने से पहले ही हैमस्ट्रिंग इंजरी के चलते बाहर हो गए थे। चेन्नई ने एलिस को 2024 के मेगा ऑक्शन में 2 करोड़ में खरीदा था।

रामकृष्ण घोष ने अपने डेब्यू मैच में 24 रन देकर 1 विकेट लिया था।

नमन अवॉर्ड्स में नोरोन्हा को एमए चिदंबरम ट्रॉफी मिली

मैकनील नोरोन्हा हाल में घरेलू क्रिकेट में शानदार फॉर्म में रहे हैं। हाल ही में BCCI के सालाना 'नमन अवॉर्ड्स' में उन्हें एमए चिदंबरम ट्रॉफी से नवाजा गया था। वे 2024-25 की कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे थे। उन्होंने महाराजा ट्रॉफी 2025 में मंगलुरु ड्रैगन्स के लिए खेलते हुए उन्होंने 10 पारियों में 253 रन बनाए और ऑफ-स्पिन से 10 विकेट भी लिए थे।

पॉइंट्स टेबल में 5वें स्थान पर सीएसके, प्ले-ऑफ की उम्मीद बरकरार

इतनी चोटों और समस्याओं के बावजूद चेन्नई सुपर किंग्स प्ले-ऑफ की रेस में बनी हुई है। टीम 11 मैचों में 12 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में 5वें स्थान पर है। प्ले-ऑफ में जगह पक्की करने के लिए चेन्नई को अपने बाकी तीनों मैच जीतने होंगे। टीम का अगला मुकाबला शुक्रवार को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में होगा।

न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए इंग्लिश टीम घोषित

क्रॉली बाहर, एमिलियो और रीव को मौका, रॉबिन्सन की वापसी

लंदन, एजेंसी

न्यूजीलैंड के खिलाफ अगले महीने लॉर्ड्स में होने वाले पहले टेस्ट मैच के लिए इंग्लैंड ने बुधवार को अपनी 15 सदस्यीय टीम घोषित कर दी है। नए नेशनल सिलेक्टर मार्कस नॉर्थ ने ऑस्ट्रेलिया से एशेज सीरीज हारने वाली टीम में 7 बदलाव किए हैं। सबसे चौंकाने वाला फैसला ओपनर जैक क्रॉली को बाहर करने का है। क्रॉली की जगह डरहम के एमिलियो गे को टीम में शामिल किया गया है। एमिलियो ने इस सीजन में 92 की औसत से 552 रन बनाए हैं। वहीं, ससेक्स के तेज गेंदबाज ऑली रॉबिन्सन की 2 साल बाद टेस्ट टीम में वापसी हुई है। इंग्लैंड को 4 जून से न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज की मेजबानी करनी है। मार्क वुड और ब्रायडन कार्स चोट के कारण उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे में ऑली रॉबिन्सन को चुना गया है। वे गस एटकिंसन और जोश टंग के साथ तेज गेंदबाजी की कमान संभालेंगे। रॉबिन्सन ने ससेक्स के लिए 6 विकेट लेकर अपनी फिटनेस और फॉर्म साबित की है। कप्तान बेन स्टोक्स भी नई गेंद से गेंदबाजी करते नजर आ सकते हैं। टीम में 2 स्पिनर्स को शामिल किया गया है। इनमें रेहान अहमद और शोएब बशीर शामिल हैं। रेहान IPL में दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा हैं, जबकि बशीर डर्बीशायर के लिए खेल रहे हैं। लॉर्ड्स में इन दोनों में से एक को प्लेइंग-11 में मौका मिल सकता है। बेन स्टोक्स (कप्तान), रेहान अहमद, गस एटकिंसन, सनी बेकर, शोएब बशीर, जैकब बेथेल, हैरी ब्रूक, बेन डकेट, मैथ्यू फिशर, एमिलियो गे, जेम्स रीव, ऑली रॉबिन्सन, जो रूट, जेमी स्मिथ (विकेटकीपर) और जोश टंग। ECB ने इस सीरीज के लिए सारा टेलर को मेंस टेस्ट टीम का फील्डिंग कोच बनाया है।

फास्ट न्यूज

महिला टी-20 वर्ल्ड कप का वॉर्म-अप शेड्यूल जारी

मुंबई। ICC ने महिला टी-20 वर्ल्ड कप 2026 के वॉर्म-अप मैचों का शेड्यूल जारी कर दिया है। मुख्य टूर्नामेंट से पहले सभी 12 टीमें 6 से 10 जून के बीच अभ्यास मैच खेलेंगी। भारतीय महिला टीम अपने दोनों वॉर्म-अप मैच कार्डिफ में खेलेगी। टीम इंडिया का सामना इंग्लैंड और वेस्टइंडीज से होगा। टूर्नामेंट 12 जून से एजबेस्टन में शुरू होगा। भारत अपना पहला ग्रुप मैच 14 जून को पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगा।

एअर इंडिया ने 6 इंटरनेशनल रूट्स पर फ्लाइट्स कैंसिल की

नई दिल्ली। एअर इंडिया ने अपनी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर कटौती का फैसला लिया है। एयरलाइन ने बुधवार को बताया कि जून से अगस्त तक 6 इंटरनेशनल रूट्स की रद्द कर दी है। इसमें दिल्ली-शिकागो और मुंबई-न्यू-यॉर्क जैसे व्यस्त रूट भी शामिल हैं। इसके अलावा 23 इंटरनेशनल रूट्स पर फ्लाइट्स की संख्या घटाई है। टाटा ग्रुप की एयरलाइन कंपनी ने बताया कि कुछ देशों के ऊपर से उड़ानों पर लगी पाबंदी और जेट फ्यूल की बढ़ती कीमतों से इन रूटों पर विमान उड़ाना घाटे का सौदा साबित हो रहा है। ईरान-अमेरिका युद्ध के कारण कई देशों ने अपना एयरस्पेस प्रतिबंधित कर दिया है, जिससे फ्लाइट्स को लंबा चक्कर लगाकर जाना पड़ रहा है। इससे ईंधन की खपत बढ़ गई है। वहीं, ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल की वजह से विमान ईंधन (ATF) के दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं।

हंतावायरस से 3 और यात्री संक्रमित हुए

वाशिंगटन। हंतावायरस के संपर्क में आए 3 और लोगों में संक्रमण मिला है। इनमें एक अमेरिकी और एक फ्रांसीसी यात्री शामिल हैं, जो पहले अपने-अपने देश लौट चुके थे। वहीं, मैड्रिड में क्वारैंटाइन एक स्पेनिश नागरिक की शुरुआती रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। अब तक 3 यात्रियों की मौत हो चुकी है। 11 अप्रैल को एक बुजुर्ग डच यात्री की जहाज पर मौत हुई थी। उनकी पत्नी बाद में दक्षिण अफ्रीका में मृत मिलीं।

मंदाना करीमी ने 16 साल बाद भारत छोड़ा

बोलीं- अब यहां घर जैसा नहीं लगता, पहले कहा था इंडिया ने मुझे धोखा दिया

मुंबई, एजेंसी

'बिग बॉस 9' और 'लॉकअप' फेम एक्ट्रेस मंदाना करीमी ने आखिरकार भारत छोड़ दिया है। 16 साल तक हिंदुस्तान में रहने के बाद उन्होंने एक इमोशनल वीडियो शेयर कर देश को अलविदा कहा। मंदाना ने भारत को अपना 'दूसरा घर' बताया था, लेकिन पिछले कुछ समय से वे अपनी सुरक्षा और बेबाक बयानी की वजह से लगातार विवादों और सुर्खियों में बनी हुई थीं। मंदाना ने इंस्टाग्राम पर 'आस्क मी एनीथिंग' सेशन के दौरान फैंस को यह खबर दी। एक फैन ने उनसे पूछा था कि क्या उन्होंने मुंबई हमेशा के लिए छोड़ दिया है? इसके जवाब में मंदाना ने एयरपोर्ट से एक वीडियो पोस्ट किया। उन्होंने कहा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसा कह पाऊंगी, लेकिन अलविदा भारत। यह मुश्किल होने वाला है। लगभग 16 साल यहां बिताने के बाद मैं अपने दूसरे घर को पीछे छोड़ रही हूं। अब एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रही हूं, नया देश, नया घर, सब कुछ नया। एक्ट्रेस ने भारत छोड़ने की मुख्य वजह अपनी सुरक्षा को बताया है। इससे पहले बॉलीवुड हंगामा को दिए इंटरव्यू में मंदाना ने अपना दर्द साझा करते हुए कहा, पिछले दो महीनों में मुझे मुंबई में बहुत अकेलापन महसूस हुआ।

पैपराजी से बचती दिखीं एक्ट्रेस, मुंह घुमाकर वहां से निकलीं

तलाक की खबरों के बीच पहली बार नजर आईं मौनी

मुंबई, एजेंसी

मौनी रॉय अपनी पर्सनल लाइफ और पति सूरज नांबियार से तलाक की खबरों को लेकर लगातार चर्चाओं में बनी हुई हैं। कई रिपोर्ट में तो दोनों के अलग रहने तक की खबरें सामने आ रही हैं। इन चर्चाओं के बीच मौनी रॉय पहली बार सार्वजनिक रूप से नजर आईं। इस दौरान एक्ट्रेस पैपराजी से बचती नजर आईं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में मौनी रॉय बीती रात पहली बार तलाक की चर्चाओं के बीच मीडिया के सामने नजर आईं। इस दौरान मौनी को मुंबई में एक रेस्टोरेंट से अपने दोस्तों के साथ बाहर आते देखा गया। मौनी अपनी दोस्त को सुरक्षित तरीके से कार के अंदर तक लेकर आईं। इस पूरे दौरान एक्ट्रेस पैपराजी और कैमरों से बचती नजर आईं। गाड़ी में बैठने के बाद भी मौनी दूसरी तरफ अपना मुंह घुमाए रहीं। वहीं अपने हाव-भाव से एक्ट्रेस थोड़ी सी परेशान जरूर दिखीं। अभिनेत्री ने न तो फोटोग्राफरों को कोई जवाब दिया और न ही कैमरे के लिए पोज देने के लिए रुकीं। मौनी रॉय और सूरज नाम्बियार के अलग होने की खबरें इस हफ्ते की शुरुआत में तब सुर्खियों में आईं जब दोनों ने इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को अनफॉलो कर दिया। इसके अलावा दोनों ने अपनी शादी की तस्वीरें भी डिलीट कर दीं। बाद में कई मीडिया रिपोर्ट्स में तो यहां तक दावा किया गया कि दोनों का तलाक हो चुका है।

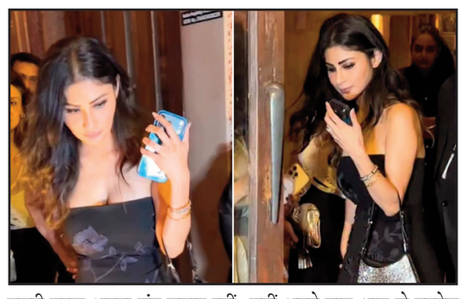

मौनी ने की झूठ न फैलाने की अपील

हालांकि, तलाक की चर्चाओं के बीच मौनी रॉय ने बीते दिन अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी साझा की। इसमें उन्होंने लोगों से झूठी खबरें न फैलाने और उनकी निजता का सम्मान करने की अपील की। साथ उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि उन्हें अपना स्पेस दें। हालांकि, मौनी ने यह पुष्टि नहीं की कि वह और सूरज अलग होने वाले हैं या उनके बीच सबकुछ ठीक है।

> वीडियो में देखा जा सकता है कि मौनी लगातार कैमरों से बचने की कोशिश कर रही थीं। कार में बैठने के बाद भी उन्होंने अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। उनके हाव-भाव से वह थोड़ी परेशान और तनाव में दिखाई दीं। उन्होंने न तो पैपराजी से बातचीत की और न ही फोटो खिंचवाने के लिए रुकीं।

आकाश अंबानी जियो प्लेटफॉर्म्स के मैनेजिंग डायरेक्टर बने

5 साल के लिए मिली जिम्मेदारी, मई-जून तक आ सकता है कंपनी का आईपीओ

नई दिल्ली, एजेंसी

रिलायंस इंडस्ट्रीज के डिजिटल आर्म 'जियो प्लेटफॉर्म्स' ने आकाश अंबानी को कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर (MD) नियुक्त किया है। यह नियुक्ति कंपनी के इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) से ठीक पहले की गई है। रेगुलेटरी फाइलिंग के मुताबिक, आकाश अंबानी का कार्यकाल 9 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो गया है और वे अगले 5 साल तक इस पद पर रहेंगे। बाजार विशेषज्ञों और रेगुलेटरी फाइलिंग के संकेतों के अनुसार, जियो प्लेटफॉर्म्स मई के अंत या जून के महीने में अपने IPO के लिए ड्राफ्ट पेपर्स (DRHP) फाइल कर सकता है। आकाश अंबानी को एमडी बनाने के फैसले को इसी लिस्टिंग की तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है। कंपनी अपनी लीडरशिप टीम को मजबूत कर निवेशकों को एक स्पष्ट विजन देना चाहती है।

जिनपिंग ने ट्रम्प से कहा- पार्टनर बनें, प्रतिद्वंद्वी नहीं

ट्रेड वॉर में कोई नहीं जीतता, ट्रम्प बोले- आपसे दोस्ती सम्मान की बात

बीजिंग, एजेंसी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने गुरुवार को बीजिंग में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में जिनपिंग ने ट्रम्प का स्वागत किया। इस दौरान ट्रम्प को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और दोनों नेताओं ने हाथ मिलाया। दोनों नेताओं के बीच 2 घंटे बैठक चली। बैठक की शुरुआत में जिनपिंग ने कहा कि पूरी दुनिया इस बैठक पर नजर लगाए हुए है। उन्होंने कहा कि दुनिया तेजी से बदल रही है और अमेरिका-चीन रिश्ते वैश्विक स्थिरता के लिए बेहद अहम हैं। जिनपिंग ने कहा कि दोनों देशों को प्रतिद्वंद्वी नहीं, बल्कि पार्टनर बनना चाहिए। उन्होंने कहा, "बार-बार साबित हुआ है कि ट्रेड वॉर में कोई विजेता नहीं होता। चीन-अमेरिका आर्थिक संबंधों का आधार आपसी लाभ और विन-विन सहयोग है।" वहीं ट्रम्प ने जिनपिंग की तारीफ करते हुए कहा, "आपका दोस्त होना सम्मान की बात है।" ट्रम्प ने कहा कि अमेरिका और चीन के रिश्ते पहले से बेहतर होने वाले हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वह दुनिया के सबसे बड़े कारोबारी नेताओं को अपने साथ लेकर चीन आए हैं। बीजिंग के टेंपल ऑफ हेवन पहुंचे ट्रम्प और जिनपिंग। अमेरिका-चीन शिखर वार्ता के बीच दोनों नेताओं ने ऐतिहासिक परिसर का दौरा किया और फोटो सेशन कराया। जिनपिंग के ताइवान पर दिए बयान के बाद ताइवान ने पलटवार किया है। ताइवान सरकार ने कहा कि ताइवान स्ट्रेट और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में अस्थिरता की सबसे बड़ी वजह चीन की सैन्य गतिविधियां हैं। ताइवान कैबिनेट की प्रवक्ता मिशेल ली ने कहा कि चीन का सैन्य खतरा ही क्षेत्रीय तनाव की अकेली वजह है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बनाए रखने के लिए रक्षा क्षमता बढ़ाना जरूरी है। यह प्रतिक्रिया उस बयान के बाद आई, जिसमें जिनपिंग ने ट्रम्प से कहा था कि ताइवान अमेरिका-चीन रिश्तों का सबसे अहम मुद्दा है। उन्होंने चेतावनी दी थी कि गलत तरीके से संभालने पर हालात खतरनाक हो सकते हैं। जिनपिंग ने यह भी कहा था कि ताइवान की स्वतंत्रता और ताइवान स्ट्रेट में शांति साथ नहीं चल सकते। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ट्रम्प के साथ चीन दौरे पर पहुंचे हैं। 1972 में रिचर्ड निक्सन के ऐतिहासिक चीन दौरे के बाद यह पहला मौका है, जब कोई अमेरिकी रक्षा मंत्री राष्ट्रपति के साथ बीजिंग गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इससे पहले 1972 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन चीन दौरे पर गए थे। उस समय रक्षा मंत्री भी उनके साथ पहुंचे थे। इसके बाद कई अमेरिकी रक्षा मंत्री चीन गए, लेकिन राष्ट्रपति के आधिकारिक दौरे में उनकी मौजूदगी नहीं रही।

अमेरिका-चीन में 9 लाख करोड़ की डील संभव

इस दौरे की सबसे बड़ी चर्चा बोइंग विमान डील को लेकर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन अमेरिकी कंपनी बोइंग से करीब 9 लाख करोड़ रुपए के विमानों की खरीद का बड़ा समझौता कर सकता है।

अगर यह डील होती है तो यह दुनिया की सबसे बड़ी एविएशन डील्स में शामिल हो सकती है। बैठक में व्यापार, टैरिफ, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और ताइवान जैसे मुद्दों पर भी बातचीत होगी। पिछले कुछ सालों में दोनों देशों के रिश्तों में काफी तनाव रहा है, इसलिए इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है।

ट्रम्प का स्वागत करने के लिए सैकड़ों स्कूली बच्चे भी पहुंचे। इनके हाथों में अमेरिका और चीन के झंडे थे।

ट्रम्प और जिनपिंग ने टेंपल ऑफ हेवन के मुख्य भवन के सामने फोटो खिंचवाई।

बढ़त : रोजाना जरूरत के सामान और गैस-बिजली के दाम बढ़े, ईरान जंग का असर

थोक महंगाई अप्रैल में 8.30%, एक महीने में दोगुनी

नई दिल्ली, एजेंसी

अप्रैल में थोक महंगाई (WPI) दोगुने से ज्यादा बढ़कर 8.30% पर पहुंच गई है। मार्च में यह 3.88% पर थी। अप्रैल में महंगाई 42 महीने में सबसे ज्यादा है। अक्टूबर 2022 में ये 8.39% पर पहुंच गई थी। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने आज यानी 14 मई को थोक महंगाई के आंकड़े जारी किए हैं। महंगाई बढ़ने की वजह रोजाना जरूरत की चीजें और फ्यूल के दाम बढ़ना है। यह बढ़ोतरी ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। यह तनाव लंबा चला तो महंगाई आगे और बढ़ सकती है। इस तनाव के वजह से क्रूड ऑयल के दाम 100 डॉलर के पार पहुंच गए हैं। थोक महंगाई के लंबे समय तक बढ़े रहने से ज्यादातर प्रोडक्टिव सेक्टर पर इसका बुरा असर पड़ता है। अगर थोक मूल्य बहुत ज्यादा समय तक ऊंचे स्तर पर रहता है तो प्रोड्यूसर इसका बोझ कंज्यूमर्स पर डाल देते हैं। सरकार केवल टैक्स के जरिए WPI को कंट्रोल कर सकती है। जैसे कच्चे तेल में तेज बढ़ोतरी की स्थिति में सरकार ने ईंधन पर एक्साइज ड्यूटी कटौती की थी। हालांकि, सरकार टैक्स कटौती एक सीमा में ही कम कर सकती है। WPI में ज्यादा वेटेज मेटल, केमिकल, प्लास्टिक, रबर जैसे फैक्ट्री से

महंगाई कैसे मापी जाती है?

भारत में दो तरह की महंगाई होती है। एक रिटेल यानी खुदरा और दूसरी थोक महंगाई होती है। रिटेल महंगाई दर आम ग्राहकों की तरफ से दी जाने वाली कीमतों पर आधारित होती है। इसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) भी कहते हैं। वहीं, होलसेल प्राइस इंडेक्स (WPI) का अर्थ उन कीमतों से होता है, जो थोक बाजार में एक कारोबारी दूसरे कारोबारी से वसूलता है।

होलसेल महंगाई के 4 हिस्से

प्राइमरी आर्टिकल, जिसका वेटेज 22.62% है। फ्यूल एंड पावर का वेटेज 13.15% और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट का वेटेज सबसे ज्यादा 64.23% है। प्राइमरी आर्टिकल के भी चार हिस्से हैं।

- फूड आर्टिकल्स जैसे अनाज, गेहूं, सब्जियां
- नॉन फूड आर्टिकल में ऑयल सीड आते हैं
- मिनरल्स
- क्रूड पेट्रोलियम

रिटेल महंगाई अप्रैल में बढ़कर 3.48% पर पहुंची

अप्रैल की रिटेल महंगाई बढ़कर 3.48% पर पहुंच गई है। इससे पहले मार्च में यह 3.40% थी। महंगाई बढ़ने की सबसे बड़ी वजह खाने-पीने की चीजों के दामों का बढ़ना है। फूड इन्फ्लेशन अप्रैल में बढ़कर 4.20% पर पहुंच गई। मार्च में यह आंकड़ा 3.87% था।

रोजाना जरूरत के सामान, फ्यूल और पावर के दाम बढ़े

रोजाना की जरूरत वाले सामानों (प्राइमरी आर्टिकल्स) की महंगाई 6.36% से बढ़कर 9.17% हो गई।

खाने-पीने की चीजों (फूड इंडेक्स) की महंगाई 1.85% से बढ़कर 1.98% पर पहुंच गई है।

फ्यूल और पावर की थोक महंगाई दर 1.05% से बढ़कर 24.71% हो गई है।

मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स की थोक महंगाई दर 3.39% से बढ़कर 4.62% रही।

भारत ने शुगर एक्सपोर्ट पर 30 सितंबर तक रोक लगाई

घरेलू सप्लाई और कीमतों को काबू में रखने के लिए फैसला, नोटिफिकेशन जारी किया

नई दिल्ली, एजेंसी

केंद्र सरकार ने चीनी के निर्यात (एक्सपोर्ट) पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये रोक देश में चीनी यानी शुगर की उपलब्धता बनाए रखने और कीमतों को काबू में रखने के लिए लगाई गई है। 13 मई से लगाई गई यह रोक 30 सितंबर 2026 तक या अगले आदेश तक लागू रहेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड (DGFT) की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, रॉ शुगर, व्हाइट शुगर और रिफाइंड शुगर की एक्सपोर्ट पॉलिसी में बदलाव किया गया है। पहले ये 'रिस्ट्रिक्टेड' (प्रतिबंधित) कैटेगरी में थे, जिन्हें अब 'प्रोहिबिटेड' (निषेध) कैटेगरी में डाल दिया गया है। इसका मतलब है कि अब बिना सरकारी इजाजत के चीनी का निर्यात नहीं किया जा सकेगा। भले ही सरकार ने ग्लोबल एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है, लेकिन कुछ खास अंतरराष्ट्रीय समझौतों को इससे बाहर रखा गया है। भारत यूरोपीय संघ (EU) और अमेरिका को CXL और TRQ कोटा के तहत चीनी का निर्यात जारी रखेगा। इसके लिए जो प्रक्रिया पहले से तय है, उसी के अनुसार शिपमेंट भेजे जाएंगे। इसके अलावा, एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम (AAS) के तहत होने वाले शिपमेंट पर भी यह पाबंदी लागू नहीं होगी। नोटिफिकेशन में यह भी साफ किया गया है कि अगर किसी दूसरे देश की सरकार भारत से चीनी की मांग करती है और वहां फूड सिक्योरिटी (खाद्य सुरक्षा) का संकट है, तो सरकार विशेष अनुमति दे सकती है। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार दूसरे देशों की जरूरतों को देखते हुए सीमित मात्रा में निर्यात को मंजूरी दे सकती है। सरकार ने फिलहाल यह रोक दो साल के लिए लगाई है। अगर 30 सितंबर 2026 तक इस बैन की अवधि को आगे नहीं बढ़ाया जाता है, तो चीनी का एक्सपोर्ट स्टेटस अपने आप दोबारा 'रिस्ट्रिक्टेड' कैटेगरी में चला जाएगा। सरकार का यह फैसला घरेलू बाजार में चीनी की कीमतों को स्थिर रखने और त्योहारी सीजन के साथ-साथ भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए अहम माना जा रहा है।

ट्रक में घुसी स्कार्पियो, परिवार के 4 लोगों की मौत

बांदा में क्रेन की मदद से निकाले गए शव, आजमगढ़ से महोबा लौट रहा था व्यवसायी परिवार

तमसा संकेत, एजेंसी

बांदा। बांदा में बेकाबू स्कॉर्पियो-N कार के सिलेंडर लदे ट्रक से टकराने से व्यवसायी, उसकी मां, दादी समेत चार लोगों की मौत हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि आधी कार डीसीएम के नीचे आ गई। गाड़ी ड्राइव कर रहे युवक के सीने में इंजन के कई पार्ट्स टूटकर घुस गए। युवक और आगे बैठी महिला के शव को निकालने के लिए क्रेन का सहारा लेना पड़ा। जबकि 2 शवों को पिछला दरवाजा खोलकर बाहर निकाला गया। हादसे में एक 19 साल की बहन भी घायल हो गई। गुरुवार सुबह 9 बजे का यह हादसा बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के किलोमीटर संख्या 47.8 पर कोतवाली देहात क्षेत्र के हथौड़ा गांव के पास हुआ है। कार सवार आजमगढ़ से महोबा के कबरई जा रहे थे। आजमगढ़ के थाना जियनपुर के गांव रामगढ़ के रहने वाले अजीत (38) परिवार समेत महोबा के कबरई कस्बे में रहते थे। यहां उनकी टायर की शॉप है। अजीत अपनी मां प्रेमशिला (55), दादी

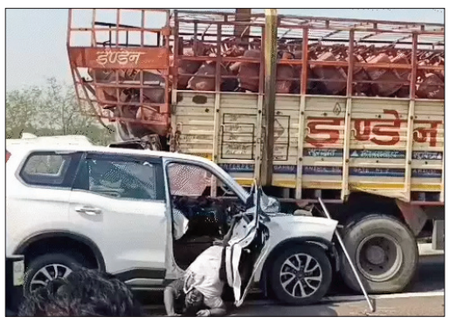

चंद्रावती (80), चाची निशा विश्वकर्मा (40) और 19 साल की चचेरी बहन रिया को लेकर अपने दोस्त की स्कॉर्पियो-N कार से आजमगढ़ अपने कुल देवता की पूजा करने आए थे। बुधवार रात करीब साढ़े 11 बजे अजीत सभी को लेकर कार से महोबा के लिए निकले थे। करीब 450 किमी का सफर तय करने के बाद गुरुवार सुबह 9 बजे वे बांदा के हथौड़ा गांव के पास पहुंचे थे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर अचानक गाड़ी चला रहे अजीत को झपकी आई। झपकी आने की वजह से स्कार्पियो बेकाबू हो गई और वह आगे चल रहे सिलेंडर लदे ट्रक में जा टकराई। टक्कर इतनी तेज थी कि आधी गाड़ी ट्रक के नीचे आग गई। 15 फीट की गाड़ी पिचककर 6 फीट की बची। गाड़ी में ड्राइवर की स्टेयरिंग, छत और सीटबेल्ट के पास लगे तीनों एयरबैग खुले लेकिन फट गए। हादसे के बाद आसपास के लोग जुटे। पुलिस को सूचना दी गई। स्कार्पियो, ट्रक में बुरी तरह फंस गई थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, गाड़ी चला रहे अजीत के शरीर में इंजन के पार्ट्स घुस गए थे। एयरबैग फटने से आगे बैठी उनकी मां प्रेमशीला और और अजीत के सिर फट गए थे। जबकि पिछली सीट पर बैठी दादी

हादसे में इनकी हुई मौत

अजीत | प्रेम शिला (अजीत की मां) | चंद्रावती (अजीत की दादी) | निशा (अजीत की चाची)

एसपी बोले- डीसीएम चालक पर दर्ज करेंगे केस

एसपी पलाश बंसल ने बताया- हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है। परिजनों से संपर्क कर उन्हें बुलाया गया है। घायल युवती सदमे में होने के कारण हादसे के बारे में कुछ भी बता पाने की स्थिति में नहीं है। उसे कानपुर रेफर किया गया है। हादसे के बाद डीसीएम चालक फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।

चंद्रावती और चाची निशा भी कार में फंसी हुई थीं। पिछली सीट पर बैठी बहन रिया गंभीर रूप से घायल थी। उसे अस्पताल पहुंचाया गया। जहां से उसे कानपुर रेफर किया गया है। बांदा पहुंचे अजीत के रिश्तेदारों ने बताया- अजीत के पिता की राम विनय विश्वकर्मा की कई साल

हादसे के बाद पुलिस ने क्रेन की मदद से किसी तरह कार को ट्रक से अलग किया गया।

क्रेन से डीसीएम उठाई तब निकाला अजीत का शव

अंदर फंसे 2 शवों को गाड़ी का पिछला दरवाजा खोलकर निकाला गया। जबकि अजीत का शव ड्राइविंग सीट और इंजन के बीच में फंसा हुआ था। आगे बैठी दादी का शव भी डैशबोर्ड और सीट के बीच फंसा था। दोनों शवों को निकालने के लिए क्रेन मंगवाया गया। एक क्रेन से ट्रक को बांधकर उठाया गया। जबकि दूसरी क्रेन से कार को पीछे खिसकाया गया। इसके बाद ड्राइविंग सीट पर फंसे अजीत के शव को बाहर निकाला गया। फिर दादी का शव निकाला जा सका।

पहले मौत हो चुकी है। दो बड़ी बहनों की शादी हो चुकी है।

गंगा एक्सप्रेसवे बनेगा उत्तर प्रदेश की प्रगति और महासमृद्धि का महामार्ग

डबल इंजन सरकार में प्रदेश में तेजी से विकसित हो रहा आधारभूत ढांचा

तमसा संकेत, संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज लखनऊ स्थित होटल द सेन्ट्रम में टाइम्स नाउ नवभारत द्वारा आयोजित 'नवनिर्माण मंच - गंगा एक्सप्रेसवेः उत्तर प्रदेश प्रगति का महामार्ग' कार्यक्रम में सहभागिता करते हुए कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे केवल एक सड़क परियोजना नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश को विकास, निवेश, रोजगार और महासमृद्धि की दिशा में आगे ले जाने वाला परिवर्तनकारी महामार्ग है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में तीव्र गति से आधारभूत ढांचे का विकास हो रहा है। बेहतर कनेक्टिविटी, आधुनिक एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, औद्योगिक कॉरिडोर तथा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में हो रहे व्यापक विकास कार्य 'विकसित उत्तर प्रदेश' के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री श्री मौर्य ने कार्यक्रम के विषय "महामार्ग से महासमृद्धि" पर अपने विचार रखते हुए कहा कि प्रदेश सरकार "विरासत भी, विकास भी" की भावना के साथ आगे

बढ़ रही है। हमारी सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण के साथ-साथ आधुनिक विकास कार्यों को भी समान प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि आज वैश्विक ऊर्जा संकट के दौर में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा ऊर्जा संरक्षण एवं राष्ट्रहित में किए गए आह्वान पर सभी नागरिकों को गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी की सोच में राष्ट्रहित सर्वोपरि है और भारत सदैव "विश्व बन्धुत्व" तथा "वसुधैव कुटुम्बकम्" की भावना का पक्षधर रहा है। उप मुख्यमंत्री ने मातृशक्ति को नमन करते हुए कहा कि समाज और राष्ट्र निर्माण में आधी आबादी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

फास्ट न्यूज

बीएचयू में एडहेसिव ब्रेसेस का होगा नया स्मार्ट उपचार

वाराणसी। ऑर्थोडॉन्टिक उपचार यानी दांतों में फिक्स्ड ब्रेसेस लगवाने वाले मरीजों के लिए एक बड़ी राहत देने वाली खोज सामने आई है। वैज्ञानिकों द्वारा विकसित एक नया "स्मार्ट एडहेसिव" न केवल ब्रेसेस के ब्रैकेट को दांतों पर अधिक मजबूती से चिपकाए रखता है, बल्कि उपचार के दौरान दांतों के इनेमल की मरम्मत करने में भी मदद करता है। यह नई तकनीक ब्रेस हटाने के समय दांतों को होने वाले नुकसान को भी काफी कम कर सकती है।

50 कर्मचारियों वाले दफ्तरों में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम

लखनऊ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल विस्तार के बाद बुधवार को अपने आवास पर पहली बार सभी मंत्रियों की बैठक ली। सीएम ने मंत्रियों से कहा, जनता के सामने उदाहरण पेश करिए। सप्ताह में कम से कम एक दिन मेट्रो, बस, ई-रिक्शा, कारपूलिंग या साइकिल का उपयोग करें। इमरजेंसी छोड़कर विदेशी यात्रा करना छोड़ना होगा। सीएम ने यह भी कहा कि जिनकार्यालयों में 50 से अधिक कर्मचारी हैं, वहां 2 दिन वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी जाए। एयर कंडीशन यानी AC का तापमान 24 से 26 डिग्री के बीच रखा जाए। लिफ्ट का भी कम से कम इस्तेमाल किया जाए। सीएम योगी ने कहा कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में ईंधन संरक्षण केवल आर्थिक आवश्यकता नहीं, बल्कि राष्ट्रीय दायित्व भी है। प्रधानमंत्री मोदी की अपील को धरातल पर उतारने के लिए सबसे पहले मंत्रिमंडल को आदर्श प्रस्तुत करना होगा।

अंसल हाउसिंग की करोड़ों रुपए की संपत्ति कुर्क

आगरा। आगरा में बकाया स्टांप शुल्क की वसूली को लेकर अंसल हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड की करोड़ों की संपत्ति कुर्क की है। जिला प्रशासन ने कार्रवाई ताजगंज थाना क्षेत्र के मौजा बगदा स्थित दफ्तर को सील कर दिया है। करीब 1.67 करोड़ रुपए स्टांप बकाया लंबे समय से जमा नहीं करने पर बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई हुई। जिला प्रशासन ने अंसल हॉउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन की कुर्की का आदेश 20 अप्रैल को जारी किया था।

राहुल की आय से अधिक संपत्ति मामले में एजेंसियां तलब

हाईकोर्ट ने सीबीआई, ईडी से जवाब मांगा, 8 हफ्ते के अंदर दाखिल करना होगा ब्योरा

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ। Rahul Gandhi की कथित आय से अधिक संपत्ति के मामले में Allahabad High Court की लखनऊ खंडपीठ ने केंद्र सरकार की कई प्रमुख जांच एजेंसियों से जवाब तलब किया है। अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) समेत अन्य संबंधित पक्षों को आठ सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को निर्धारित की गई है।

यह आदेश न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान और न्यायमूर्ति Zafeer Ahmad की खंडपीठ ने एस. विग्नेश शिशिर द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद पारित किया। याचिकाकर्ता ने अपनी अर्जी में केंद्र सरकार के Department of Personnel and Training (डीओपीटी), वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग और Ministry of Corporate Affairs को भी मामले में

पक्षकार बनाए जाने की मांग की थी।

अदालत ने इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए हाईकोर्ट ने याचिका से जुड़ी पूरी पत्रावली और अन्य दस्तावेजों को सीलबंद लिफाफे में सुरक्षित रखने का आदेश भी दिया है। अदालत के इस निर्देश के बाद मामले ने राजनीतिक और कानूनी हलकों में नई चर्चा छेड़ दी है। न्यायालय ने टिप्पणी की कि यदि शिकायत प्राप्त हो चुकी है, तो संबंधित एजेंसियां कानून के अनुसार आरोपों का सत्यापन करें और आवश्यक कार्रवाई करें। एसएफआईओ ने भी जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा, जिसे न्यायालय ने स्वीकार करते हुए सभी पक्षों को निर्धारित समय-सीमा में प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया।

याचिकाकर्ता ने सीबीआई और ईडी को भी दी शिकायत

सुनवाई के दौरान, सीबीआई के अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि याचिकाकर्ता की शिकायत प्राप्त हो चुकी है और जांच संबंधी जवाब अगली तारीख तक जमा कर दिया जाएगा। इसी तरह, ईडी ने भी कहा कि शिकायत मिलने के बाद आरोपों का परीक्षण किया जा रहा है और इसकी प्रगति रिपोर्ट अगली सुनवाई में दाखिल की जाएगी। न्यायालय ने टिप्पणी की कि यदि शिकायत प्राप्त हो चुकी है, तो संबंधित एजेंसियां कानून के अनुसार आरोपों का सत्यापन करें और आवश्यक कार्रवाई करें। एसएफआईओ ने भी जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा, जिसे न्यायालय ने स्वीकार करते हुए सभी पक्षों को निर्धारित समय-सीमा में प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया।

कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता ने डाली है याचिका

यह याचिका कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर की ओर से दाखिल की गई है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि राहुल गांधी और उनके परिवार की संपत्तियां घोषित आय से अधिक हैं। याचिका में मामले की केंद्रीय जांच एजेंसियों से निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई है। आज होने वाली सुनवाई में अदालत सबसे पहले याचिका की ग्राह्यता (Maintainability) पर विचार करेगी। यानी कि यह तय किया जाएगा कि मामले में दाखिल याचिका सुनवाई के योग्य है या नहीं। इसके बाद ही आगे की कानूनी प्रक्रिया तय होगी।

उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा 712.40 लाख रूपये की लागत से 08 संरक्षित स्मारकों का कार्य पूरा कराया गया

ऐतिहासिक एवं धार्मिक पुरास्थल युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा के स्रोत : जयवीर सिंह

तमसा संकेत, संवाददाता

लखनऊ। संस्कृति विभाग के अधीन पुरातत्व निदेशालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में बजट के सापेक्ष जारी वित्तीय स्वीकृतियाँ एवं किये गये कार्यों की प्रगति आदि के लिए प्रावधानित बजट 08 करोड़ रूपये से संरक्षित स्मारकों एवं पुरास्थलों का कन्जर्वेशन एवं रेस्टोरेशन कार्य कराया है। इसके तहत मार्च 2026 तक 712.40 लाख रूपये की धनराशि व्यय हुई है। यह जानकारी प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि संरक्षित स्मारक शिव मंदिर, अलावलपुर सीतापुर का 93.76 लाख रूपये व्यय कर पेन्टिंग कन्जर्वेशन सहित सभी कार्य पूर्ण कराये गये है। इसी प्रकार संरक्षित स्मारक तुलारामतालाब एवं शिव मंदिर, फतेहपुर का 133.83 लाख रूपये से तालाब की सीढ़ियों का रेस्टोरेशन सहित सभी कार्य पूरे कराये गये है। जयवीर सिंह ने बताया कि संरक्षित पुरास्थल हुलासखेड़ा, मोहनलालगंज,

लखनऊ के समस्त कार्य 167.74 लाख रूपये से पूर्ण हो चुकें है। इसके अलावा संरक्षित स्मारक कबीरदास की समाधि एवं मजार जनपद संतकबीर नगर का कार्य 16.78 लाख रूपये से पूरा कराये गये है। इसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण संरक्षित स्मारक स्थलों पर सांस्कृतिक सूचना पटटों की स्थापना का कार्य 18.31 लाख रूपये की धनराशि से कराया गया है। जयवीर सिंह ने बताया कि संरक्षित स्मारक उत्खनन स्थल बनरसिहा कला, जनपद महाराजगंज का कार्य 146.73 लाख रूपये तथा संरक्षित स्मारक टिकैत राय शिव मंदिर बिठूर कानपुर नगर का कार्य 78.96 लाख रूपये तथा संरक्षित स्मारक टिकैत राय शिव मंदिर बिठूर कानपुर नगर का कार्य भी 56.29 लाख रूपय की धनराशि से पूरा कराया गया है। जयवीर सिंह ने बताया कि प्रदेश में ऐतिहासिक महत्व के प्राचील स्थल बड़ी संख्या में स्थित है, जो सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से अतिमहत्वपूर्ण है।

चकरपुर मंडी में लगी भीषण आग

दुकानदार बोले- घंटेभर बाद आई फायर ब्रिगेड, 44 दुकानें जलीं, 50 फीट ऊंची लपटें उठीं

तमसा संकेत, एजेंसी

कानपुर। कानपुर के सचेंडी स्थित चकरपुर सब्जी मंडी में गुरुवार दोपहर अचानक भीषण आग लग गई। आग की शुरुआत चबूतरा नंबर-6 स्थित एक आढ़त से हुई और देखते ही देखते उसने पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी तेजी से फैली कि 44 दुकानें धू-धू कर जलने लगीं। मौके पर मौजूद आढ़तियों ने पहले खुद आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन लपटें बढ़ती देख दुकानों को छोड़कर जान बचाकर भागना पड़ा। करीब 50 फीट ऊपर तक आग की लपटें देखी गईं। महिमा फ्रूट कंपनी के मालिक मनोज ने कहा- फायर ब्रिगेड सूचना के 1 घंटे बाद आई। हमारे 1 हजार कैरेट अनार जल गए हैं। करीब 15 लाख का नुकसान हुआ है। मंडी समिति के पास आग से बचाव के कोई इंतजाम नहीं हैं। फायर ब्रिगेड के मुताबिक, पहले दो दमकल गाड़ियों को भेजा गया, लेकिन आग की गंभीरता को देखते हुए बाद में 12 फायर टेंडर मौके पर लगाए गए। करीब तीन घंटे में आग पर काबू पा लिया गया। कोई जनहानि नहीं हुई

चश्मदीदों के मुताबिक, चबूतरा नंबर-6 पर स्थित मुन्ना ब्रदर्स की फल आढ़त में दोपहर अचानक आग लग गई। कुछ ही देर में आग आसपास की दुकानों तक पहुंच गई। मंडी में रखी प्लास्टिक की कैरेट के कारण आग तेजी से फैलती चली गई। हालात ऐसे हो गए कि आग की लपटें करीब 40 से 50 फीट तक ऊंची दिखाई देने लगीं, जिन्हें दूर से भी देखा गया। शुरुआत में कई आढ़ती बाल्टियों और पाइप से पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन कुछ ही मिनटों में आग बेकाबू हो गई। प्राथमिक जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है, हालांकि अधिकारियों ने कहा है कि विस्तृत जांच के बाद ही स्पष्ट कारण सामने आएगा। इंस्पेक्टर दीनानाथ मिश्रा ने बताया कि फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। आढ़तियों ने आग से करोड़ों रुपए के नुकसान की आशंका जताई है। फिलहाल प्रशासन दुकानों के नुकसान का आकलन कराने में जुटा है। महिमा फ्रूट कंपनी के मालिक मनोज ने कहा- फायर ब्रिगेड सूचना के 1 घंटे बाद आई। हमारे 1 हजार कैरेट अनार जल गए हैं। करीब 15 लाख का नुकसान हुआ है। एक अन्य आढ़ती ने बताया- हमारी दुकान में लैपटॉप, खाताबुक, टिनशेड वगैरह जल गए हैं। आग से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। मंडी में आग बुझाने का कोई उपकरण नहीं है। अगर होते तो इतना नुकसान नहीं होता। मंडी सीमित सिर्फ टैक्स लेना जानता है, आग से करोड़ों का नुकसान हुआ है। मंडी सचिव विजिन बालियान ने बताया- करीब 12 बजे शार्ट सर्किट से आग लगी। आग लगते ही फायर बिग्रेड को सूचना दी गई। छह नंबर चबूतरे में करीब 44 दुकाने थीं। नंबर से लेकर 44 नंबर दुकान तक आग लगी है।

विरोध : पीएम पर अजेन्द्र सिंह लोधी की टिप्पणी को बताया शर्मनाक, कानपुर में बोलीं- माफी मांगे

सपा सांसद के खिलाफ बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन

- राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन महिलाओं ने डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह को सौंपा।
- हमीरपुर से सपा सांसद अजेन्द्र सिंह लोधी के खिलाफ महिलाओं ने नारेबाजी की।

तमसा संकेत, एजेंसी

कानपुर। कानपुर में गुरुवार को बीजेपी महिला मोर्चा ने हमीरपुर से सपा सांसद अजेन्द्र सिंह लोधी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में महिला मोर्चा की कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचीं और राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सांसद के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कार्रवाई की मांग उठाई। प्रदर्शन का नेतृत्व महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष पूनम कपूर और

सपा सांसद ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए कहा था- देश की जनता ने कभी न तो ऐसा देश विरोधी प्रधानमंत्री देखा और न ही भविष्य में ऐसा पीएम देखने को मिलेगा। वो खुद तो खर्च कर विदेश यात्रा करते हैं और जनता से कहते हैं कि विदेश घूमने मत जाओ।

जिला अध्यक्ष उत्तर अनिल दीक्षित ने किया। दोनों नेताओं ने जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और सांसद के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई। सपा सांसद ने ये बयान सोमवार को कलेक्ट्रेट में दिया था। वो कई समर्थकों के साथ स्मार्ट मीटर के विरोध समेत 11 मांगों का ज्ञापन देने गए थे। पूनम कपूर ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ इस प्रकार की टिप्पणी स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि इस बयान का राजनीतिक असर भी देखने को मिलेगा और आने वाले चुनावों में इसका जवाब जनता देगी। उन्होंने कहा कि फिलहाल शांतिपूर्ण तरीके से विरोध दर्ज कराया गया है, लेकिन यदि सांसद माफी नहीं मांगते हैं तो महिला मोर्चा आगे बड़ा आंदोलन करेगा। प्रदर्शन में महिला मोर्चा की उत्तर और दक्षिण जिला इकाइयों की कई कार्यकर्ता मौजूद रहीं, जिनमें अनीता त्रिपाठी, मधु तिवारी, प्रेमलता तिवारी, सपना शर्मा और वंदना सहित अन्य पदाधिकारी शामिल थीं।

'प्रधानमंत्री पर टिप्पणी से आहत हैं कार्यकर्ता'

प्रदेश उपाध्यक्ष पूनम कपूर ने कहा कि हमीरपुर सांसद द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस्तेमाल की गई भाषा की हर स्तर पर निंदा हो रही है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी प्रधानमंत्री की मां को लेकर टिप्पणी की गई थी और अब इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर राजनीतिक मर्यादाओं की सीमाएं पार की गई हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी महिला मोर्चा की मांग है कि सांसद सार्वजनिक रूप से माफी मांगें। यदि ऐसा नहीं किया जाता है।

पृष्ठ 01 का शेष...

अखिलेश के ...

अंतिम संस्कार कराने वाले पंडित ध्रुव कुमार तिवारी ने से कहा था- अगर अखिलेश यादव या उनके बेटे से मुखाग्नि दिलाई जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। इससे पहले, प्रतीक की अंतिम यात्रा निकाली गई। शिवपाल के बेटे आदित्य ने शव को कंधा दिया। प्रतीक एनिमल लवर थे। शव वाहन पर उनकी डॉग्स और बंदर के साथ वाली तस्वीर लगाई गई। प्रतीक का बुधवार सुबह 6 बजे 38 साल की उम्र में निधन हुआ था। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मौत की वजह कार्डिएक अरेस्ट बताई गई। उनके शरीर पर 6 चोटें पाई गईं, जो मौत से पहले लगी थीं। इनमें 3 चोटें 7 दिन पुरानी और 3 चोटें एक दिन पुरानी थीं। उनका विसरा सुरक्षित रखा गया है। प्रतीक, मुलायम यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे थे। उनकी पत्नी अपर्णा यादव भाजपा नेता हैं। इस वक्त राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं। डॉक्टरों के मुताबिक, प्रतीक फेफड़ों की गंभीर बीमारी पल्मोनरी एम्बोलिज्म की चपेट में थे। इसमें खून का थक्का फेफड़ों में फंसकर ब्लड सर्कुलेशन को रोक देता है। प्रतीक को 13 दिन में दो बार दिल का दौरा (हार्ट अटैक) पड़ा था। इससे पहले, 30 अप्रैल को लखनऊ एयरपोर्ट पर चलते-चलते गिर पड़े थे। तब मेदांता हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने बताया था कि प्रतीक को दिल का दौरा पड़ा है। गुरुवार सुबह प्रतीक यादव के शव को अंतिम दर्शन के लिए घर में रखा गया। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरि महाराज, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने प्रतीक को श्रद्धांजलि दी। ब्रजेश पाठक पत्नी नम्रता के साथ पहुंचे थे। शिवपाल यादव और डिंपल यादव ने भी अंतिम दर्शन किए। घर से 5 किमी दूर बैकुंठ धाम तक शव यात्रा निकाली गई। हजारों समर्थक साथ-साथ चले और 'प्रतीक यादव अमर रहें' के नारे लगाए। प्रतीक के घर से कुछ दूरी पर ही सपा कार्यालय है। शव को कुछ देर के लिए वहां जमीन पर रखा गया। परंपरा के अनुसार, श्मशान घाट पहुंचने से पहले शव को पांच बार जमीन पर रखा जाता है। शव यात्रा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह भी शामिल हुए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और मंत्री दिनेश सिंह श्मशान घाट पहुंचे। अखिलेश यादव और शिवपाल के अगल-बगल प्रतीक की दोनों बेटियां प्रथमा और पद्मजा बैठीं। अखिलेश छोटी बेटी पद्मजा से बातचीत करते रहे। उन्होंने बच्ची को चॉकलेट भी दी। सपा प्रमुख के बेटे अर्जुन उनके पीछे बैठे। दो कुर्सी छोड़कर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी बैठे थे। डिप्टी सीएम जब जाने लगे, तो अखिलेश ने उनसे मुलाकात की और हाथ भी मिलाया।

सबरीमला में ...

केंद्र के मुताबिक, यह मामला न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर है। सबरीमाला मंदिर मामले पर 7 अप्रैल से सुनवाई शुरू हुई है। पहले 3 दिन, 9 अप्रैल तक सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र सरकार ने महिलाओं की एंट्री के विरोध में दलीलें रखीं। सरकार ने कहा था कि देश के कई देवी मंदिरों में पुरुषों की एंट्री भी बैन है, इसलिए धार्मिक परंपराओं का सम्मान किया जाना चाहिए।

चारधाम यात्रा में ...

लेकिन लगातार बढ़ते मौत के आंकड़े यात्रा मार्ग पर स्वास्थ्य चुनौतियों और हाई एल्टीट्यूड से जुड़ी परेशानियों की गंभीरता भी दिखा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि अधिकांश मौतें हार्ट अटैक, हाई एल्टीट्यूड सिकनेस, हाइपरटेंशन और अन्य स्वास्थ्य कारणों से हुई हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार चारधाम यात्रा में अब तक हुई अधिकांश मौतें स्वास्थ्य खराब होने, हार्ट अटैक और हाई एल्टीट्यूड सिकनेस जैसी समस्याओं के कारण हुई हैं।यात्रा मार्ग ऊंचाई वाले क्षेत्रों से होकर गुजरता है, जहां ऑक्सीजन का स्तर कम होने और लगातार चढ़ाई की वजह से बुजुर्गों और पहले से बीमार यात्रियों की तबीयत बिगड़ने के मामले सामने आ रहे हैं। चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले सरकार ने कई समीक्षा बैठकें की थीं। सभी विभागों को यात्रा शुरू होने से पहले तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए थे। सरकार का दावा है कि यात्रा मार्ग पर स्वास्थ्य सेवाओं, डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। यात्रियों के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई थी, जिसमें बुजुर्गों, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर और हृदय रोग से पीड़ित लोगों को स्वास्थ्य जांच कराने की सलाह दी गई थी। स्वास्थ्य मंत्री ने भी यात्रियों से सावधानी बरतने और शरीर में परेशानी होने पर तुरंत रुकने की अपील की है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. सुबोध उनियाल ने कहा कि कई यात्री शरीर के संकेतों को नजरअंदाज कर तेजी से यात्रा पूरी करने की कोशिश करते हैं।

सुप्रीम कोर्ट का ...

इस कानून के मुताबिक, CEC और EC की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और एक केंद्रीय मंत्री वाली समिति करेगी। पहले सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम व्यवस्था में इसमें भारत के CJI को भी शामिल किया था। याचिकाकर्ताओं का दावा- 2023 का कानून चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को कमजोर करता है। याचिकाओं में कहा गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़ा 2023 का कानून चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को कमजोर करता है। इसमें चयन समिति से भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को हटा दिया गया है। दरअसल, 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने 'अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ' मामले में कहा था

यूपी में आंधी-तूफान, टिनशेड के साथ 50 फीट उड़ा युवक

100 मीटर दूर खेत में गिरा, 24 घंटे में 100 मौतें, 2000 से ज्यादा गांवों की बिजली गुल

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ/वाराणसी/प्रयागराज/कानपुर। यूपी में आंधी-तूफान और तेज बारिश की वजह से पिछले 24 घंटे में 100 लोगों की मौत हो गई। बाराबंकी, सीतापुर और देवरिया समेत कई जिलों के 2000 से ज्यादा गांवों की बिजली गुल हो गई। बुधवार शाम बरेली में 90 की रफ्तार में चली आंधी में टिन शेड के साथ 50 साल का युवक करीब 50 फीट हवा में उड़ गया। वह 100 मीटर दूर खेत में गिरा। उसका हाथ टूट गया। अस्पताल में इलाज के बाद उसे घर भेज दिया गया। प्रयागराज में सबसे ज्यादा 21, भदोही में 17 मौतें हुईं। मिर्जापुर में आंधी और बिजली गिरने से 15 लोगों की जान चली गई। फतेहपुर में 10, बदायूं में 6, प्रतापगढ़ और बरेली में 4-4 मौतें हुईं। बुधवार को गाजियाबाद, वाराणसी, अयोध्या समेत 30 जिलों में बारिश हुई। मथुरा, उन्नाव और प्रयागराज में आंधी-बारिश के साथ ओले गिरे। कई जगह पेड़

टूटकर गिर गए। बिजली के खंभे उखड़ गए। दीवार गिरने से गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। आज यानी गुरुवार को मौसम साफ है। तेज धूप निकली है। मौसम विभाग ने आज 51 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान तेज हवाएं भी चल सकती हैं। आज से पश्चिमी विक्षोभ कमजोर पड़ने लगेगा। इससे प्रदेश में मौसम साफ होने लगेगा। तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी होगी। दिन के साथ रात में गर्मी पड़ेगी। 16 मई से बुंदेलखंड और दक्षिणी जिलों में लू चलने और तपिश बढ़ने की भी संभावना है।

तमसा संकेत
tamsa.newslko@gmail.com

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक विद्या देवी द्वारा कृष्णा डाइनेस्टी प्रिंटिंग प्रेस म0 न0 195 सेक्टर 6-बी, वृन्दावन योजना, रायबरेली रोड लखनऊ-226 029 (उ0प्र0) से मुद्रित व प्रकाशित।

सम्पादक : विद्यादेवी

समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा

समाचार पत्र में प्रकाशित लेख, राजनीतिक विश्लेषण, लेखकों के अपने विचार हैं। सम्पादक का इन विचारों से सहमत होना आवश्यक नहीं हैं।
मो0- 9415799533
R.N.I. NO. UPHIN/2021/83676